छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 235 ■ अम्बिकापुर, रविवार 13 सितम्बर 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

न्यायालय को गुमराह कर फर्जी पट्टे से जमानत लेनेवाले रैकेट का पर्दाफाश

मास्टरमाइंड सहित 7 गिरफ्तार, लैपटॉप-प्रिंटर-स्कूटी जब्त

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा पुलिस ने न्यायालय में फर्जी पट्टा और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए आरोपियों की अवैध रूप से जमानत कराने वाले संगठित गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देशन और नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में थाना कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए कुल 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 05 नग फर्जी किसान पट्टा, 01 फर्जी आधार कार्ड, 06 मोबाइल फोन, 01 होंडा एक्टिवा स्कूटी सीजी 15 डीयू 8688, 01 लैपटॉप, 02 प्रिंटर, की-बोर्ड और माउस जब्त किया है। जब्त उपकरणों से ही फर्जी पट्टे तैयार किए जाते थे।

मामले का खुलासा 11 सितंबर को हुआ। थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति न्यायालय परिसर में जरूरतमंद आरोपियों से संपर्क कर पैसा लेकर फर्जी पट्टा पुस्तिका और आधार कार्ड के माध्यम से जमानत करा रहे हैं और अभी न्यायालय में ही मौजूद हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी और सीएसपी राहुल बंसल के नेतृत्व में कोतवाली और साइबर सेल की टीम मौके पर रवाना हुई।

कला केंद्र मैदान में मिले मास्टरमाइंड सहित अन्य

मुखबिर के बताए हुलिए के आधार पर टीम ने कला केंद्र मैदान के चबूतरा के पास दबिश दी, जहां 05 लोग संदिग्ध अवस्था में मिले। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम बुधराम पिता स्व. रनसाय गोंड 55 वर्ष निवासी अजबनगर थाना जयनगर जिला सूरजपुर, अजय मानिकपुरी उर्फ जयलाल पिता स्व. सुरजन मानिकपुरी 40 वर्ष निवासी बलसेंडी थाना गांधीनगर, रामेश्वरी यादव पति महेश्वर यादव 30 वर्ष निवासी लब्जी थाना गांधीनगर, दशमेत गोंड पति बुधराम गोंड 40 वर्ष निवासी अजबनगर और ममता पैकरा उर्फ बिलासो पिता शिवधर पैकरा 29 वर्ष निवासी बेलसेंडी कल्याणपुर थाना गांधीनगर बताया।

कार्रवाई में ये रहे शामिल

पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, अदीप प्रताप सिंह, विवेक पांडे, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, विकास सिन्हा, आरक्षक देवेंद्र पाठक, संजीव चौबे, मनीष सिंह, वीरेंद्र पैकरा, महिला आरक्षक पूनम पैकरा, स्मिता रागिनी और किरण अमलावती की सराहनीय भूमिका रही।

स्कूटी की डिक्की में मिले फर्जी पट्टे

संदेह होने पर पुलिस ने तलाशी ली तो पास खड़ी एक्टिवा स्कूटी की डिक्की से 05 नग किसान पट्टा और 01 आधार कार्ड बरामद हुए। प्रथम दृष्टया सभी पट्टों पर फर्जी सील लगी थी और हस्ताक्षर नहीं थे। कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ये फर्जी दस्तावेज न्यायालय में जमानत के लिए उपयोग करते थे और इसके एवज में आरोपियों से मोटी रकम वसूलते थे। वे कई बार इसी तरीके से जमानत करा चुके हैं। आरोपियों ने बताया कि ये फर्जी पट्टे उन्हें अंबिकापुर का कुख्यात पट्टा दलाल राज जायसवाल उपलब्ध कराता है। निशानदेही पर पुलिस ने राज जायसवाल पिता स्व. भोलानाथ जायसवाल 34 वर्ष निवासी वार्ड नं. 23 घुटरापारा को हिरासत में लिया। अलग-अलग मेमोरेंडम कथन में बुधराम और राज जायसवाल ने खुलासा किया कि फर्जी पट्टे नवापारा निवासी शशिभूषण सिंह तैयार करता है।इसके बाद पुलिस ने अंतिम आरोपी शशिभूषण सिंह पिता शिव कुमार सिंह 36 वर्ष निवासी वार्ड नं. 16 नवापारा को भी गिरफ्तार कर लिया। शशिभूषण ही अपने घर पर लैपटॉप और प्रिंटर से फर्जी पट्टा बनाता था और पूरे गिरोह को सप्लाई करता था। आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।

अपराध दर्ज, पुलिस ने की ये अपील

सभी आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 639/26 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। सरगुजा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि बिना जान-पहचान के किसी भी व्यक्ति को जमानत के लिए अपना मूल पट्टा या ऋण पुस्तिका कतई न दें। यदि आरोपी फरार हो जाता है तो आपका पट्टा जब्त हो सकता है और आप भी फर्जीवाड़े का शिकार हो सकते हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पट्टा मांगे जाने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।

प्रदूषण का काला सच, परसा कोल माइंस से साल्ही नदी में छोड़ा जा रहा कोयले का पानी

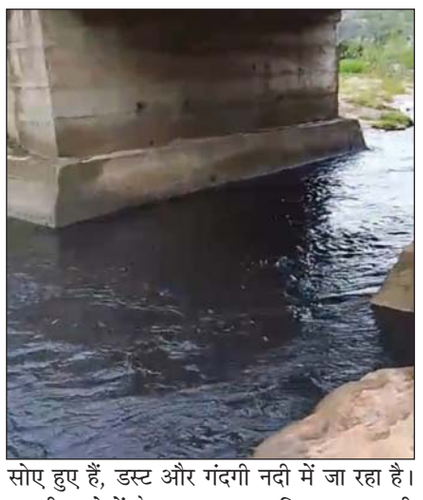

छ.ग. फ्रंटलाइन उदयपुर/अंबिकापुर। हसदेव क्षेत्र में संचालित परसा कोल माइंस में एक बार फिर गंभीर पर्यावरणीय लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि खदान से निकलने वाला कोयला युक्त दूषित काला पानी सीधे साल्ही नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे पूरी नदी का पानी काला पड़ गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने शनिवार 11 सितंबर की सुबह नदी के पास पहुंचकर इसका वीडियो बनाया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नदी में बह रहा पानी पूरी तरह से काला और छूने लायक भी नहीं है। ग्रामीण का कहना है कि पूर्व दिशा में स्थित कोयला खदान से यह गंदा पानी लगातार नदी में बहाया जा रहा है। वीडियो में ग्रामीण पर्यावरण विभाग से अपील करते हुए सुनाई दे रहा है कि जिला सरगुजा के क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लें और क्रमबद्ध तरीके से खदानों का निरीक्षण करना अनिवार्य है। ग्रामीण ने कहा कि अधिकारी सोए हुए हैं, डस्ट और गंदगी नदी में जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह दूषित काला पानी साल्ही नदी से आगे अटेम नदी में मिल रहा है। बताया जा रहा है कि कोल कंपनी ने साल्ही नदी में पुलिया का निर्माण भी किया है, जिसके नीचे से यही काला पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घटना से मछलियों और अन्य जलीय जीवों पर संभावित खतरे को लेकर ग्रामीणों में भारी चिंता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पर्यावरण विभाग तत्काल मौके पर पहुंचकर पानी के सैंपल लेकर वैज्ञानिक जांच कराए और खदान प्रबंधन पर कार्रवाई करे। गौरतलब है कि हसदेव क्षेत्र में खनन को लेकर पहले भी लगातार विरोध होता रहा है। परसा कोल माइंस का संचालन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर खदान से निकलने वाले पानी के ट्रीटमेंट और निस्तारण की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

संवेदनशील जगहों पर विजिबल पुलिसिंग और असामाजिक तत्वों पर करें सख्त कार्रवाई

डीआईजी और एसएसपी सरगुजा ने ली थाना-चौकी प्रभारियों की क्राइम मीटिंग

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में लंबित अपराध, शिकायतें, मर्ग, चालान, खात्मा, म्यूल अकाउंट और पीओएस के मामलों की समीक्षा कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। एसएसपी ने कहा कि सभी थानों में सीसीटीएनएस पोर्टल में एंट्री अपडेट रखी जाए। ई-साक्ष्य, मालखाना एंट्री और ई-सिग्नेचर के लिए प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

बैठक में थाना-चौकी में लंबित पुराने अपराध, मर्ग, शिकायत, गुम इंसान और खात्मा के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने को कहा गया। लघु अधिनियम और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई बढ़ाने और जिला बदर योग्य अपराधियों का प्रतिवेदन तत्काल भेजने के निर्देश दिए गए। सीसीटीएनएस और डिजिटल पोर्टल के तहत ई-साक्ष्य, मालखाना एंट्री, वीसीएनबी एंट्री और मेडिकल रिपोर्ट ऑनलाइन भेजना अनिवार्य किया गया। पोर्टल से मेडिकल रिपोर्ट भेजने, सीसीटीएनएस में आईआईएफ-1 से आईआईएफ-6 तक ऑनलाइन एंट्री पूरी करने और एफआईआर अपलोड करने से पहले ई-सिग्नेचर करने को कहा गया। कोर्ट से जारी समन, वारंट, नोटिस की तामिली प्राथमिकता से कर ई-समन को ऑनलाइन पेश करने के निर्देश दिए गए। थानों में जब्त लावारिस वाहनों की नीलामी और एनडीपीएस व राजसात के मामलों में तेज कार्रवाई करने को कहा गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए गुम इंसान के मामलों में घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कर बरामदगी करने को कहा गया। भीड़-भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील जगहों पर विजिबल पुलिसिंग और प्रभावी गश्त बढ़ाने, असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। गंभीर अपराधों में एफएसएल टीम को मौके पर भेजना अनिवार्य किया गया। साइबर जागरूकता अभियान के तहत सभी थाना-चौकी प्रभारियों को रोजाना स्कूल-कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा गया। 17 सितंबर को सेवा संकल्प अभियान के तहत सभी पुलिस कार्यालयों में दीप प्रज्ज्वलित करने और अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए।

बैठक के अंत में एसएसपी ने डिजिटलीकरण के लिए पुलिस मुख्यालय से मिले उपकरण - ई-सिग्नेचर पेन, डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस, क्यूआर कोड स्कैनर, लाइव स्कैनर, थंब मशीन सभी थाना प्रभारियों को दिए और उनके रखरखाव और सही उपयोग के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी, नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल, एसडीओपी तुल सिंह पट्टावी, डीएसपी सुरेश भगत, डीएसपी राकेश बघेल, रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत सहित जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारी मौजूद रहे।

आम आदमी पार्टी को सरगुजा में बड़ा झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 120 कांग्रेस में शामिल, टीएस सिंहदेव ने दिलाई सदस्यता

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। लोकसभा चुनाव से पहले सरगुजा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में सरगुजा इकाई के 120 कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। शुक्रवार को राजीव भवन अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सभी को कांग्रेस की सदस्यता की रसीद और पट्टिका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस में शामिल होने वालों में आप के प्रदेश संगठन मंत्री अलेक्जेंडर केरकेट्टा, सरगुजा जिलाध्यक्ष सीताराम मानिकपुरी, जोन सह प्रभारी नूर हसन अली सहित जिला संगठन के 120 कार्यकर्ता शामिल हैं। साथ ही कोरबा लोकसभा प्रभारी अध्यक्ष विजय नायक ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सभी कार्यकर्ता शैला नृत्य और गाजे-बाजे के साथ रैली के रूप में राजीव भवन पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि देश और प्रदेश की परिस्थितियों के अनुरूप एक विचार के साथियों में यह आपसी समझ बनी है कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए एक साथ आना जरूरी है। उसी दिशा में आप सभी के कांग्रेस में जुड़ने का स्वागत है। आज जब हम सत्ता में नहीं हैं, तब आपका हमारे साथ जुड़ना आपके निस्वार्थ भाव को दर्शाता है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि राजेंद्र बहादुर सिंह जैसे जुझारू नेतृत्वकर्ता के आने से पार्टी और मजबूत होगी। आम आदमी पार्टी से आए सभी साथियों को बूथ से लेकर जिले तक कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी निभानी है। इस अवसर पर राजेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि मैंने अकेले ही आप छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि टुकड़ों में बंटकर भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए सभी ने कांग्रेस और टीएस सिंहदेव में आस्था जताते हुए कांग्रेस ज्वाइन की है। मुझे अपनी पुरानी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आज की परिस्थितियों से उबरने के लिए समान विचारधारा के लोगों को साथ आना ही पड़ेगा। कार्यक्रम को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पूर्व उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता, अलेक्जेंडर केरकेट्टा, नूर हसन अली ने भी संबोधित किया। इस दौरान हेमंत सिन्हा, विनय शर्मा, मो. इस्लाम, प्रशांत सिंह, इंद्रजीत सिंह धंजल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

संत गहिरा गुरु विवि में साइबर क्राइम मुक्त छत्तीसगढ़ का लिया गया संकल्प

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा के सिटी कैंपस दर्रीपारा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में 12 सितंबर को साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय परिवार को बढ़ते साइबर अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास धर्मस्व विभाग राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेंद्र लाकपाले ने की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा और विशेष अतिथि के रूप में सरगुजा पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल मौजूद रहे।

तकनीकी सत्र में साइबर विशेषज्ञों अभय तिवारी उप निरीक्षक, अनुज जायसवाल, मंगल पांडे नव विहान जिला संयोजक और अमन पुरी ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध के विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार से बताया। विशेषज्ञों ने ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल और लिंक, ओटीपी-बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया अपराध, फिशिंग, साइबर बुलिंग, फर्जी वेबसाइट और डिजिटल ठगी जैसे अपराधों से बचने के उपाय समझाए।

विशेषज्ञों ने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, पासवर्ड, बैंक डिटेल, पिन या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा न करें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें। किसी भी तरह की ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस को सूचना दें। कुलपति प्रो. लाकपाले ने कहा कि डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक, खासकर युवाओं की भी जिम्मेदारी है। विद्यार्थी इस जागरूकता का संदेश समाज के अन्य वर्गों तक पहुंचाएं। मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल और पुलिस अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के इस प्रयास की सराहना की और सुरक्षित और साइबर अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विद्युत अधिकारी-कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग को लेकर आज छत्तीसगढ़ विद्युत अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन अधिकार मंच के बैनर तले अम्बिकापुर क्षेत्र में संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन मुख्य अभियंता अंबिकापुर क्षेत्र यशवंत शिलेदार को सौंपा गया। ज्ञापन में ऊर्जा विभाग के 6 अक्टूबर 2023 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि एक जनवरी 2004 अथवा उसके बाद नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों को नई अंशदायी पेंशन योजना से पुरानी पेंशन प्रणाली में अंतरित करने की सैद्धांतिक सहमति दी गई थी। इसके बावजूद अब तक लागू नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष है। अधिकार मंच ने बताया कि पावर कंपनी के सभी 12 अधिकारी-कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 11 सितम्बर को सभी संयंत्रों व क्षेत्रीय मुख्यालयों में आमसभा व ज्ञापन कार्यक्रम हो रहा है। इसके बाद मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंदोलन के अगले चरण में 5 अक्टूबर को कंपनी मुख्यालय डंगनिया, रायपुर में सामूहिक प्रदर्शन एवं विशाल आमसभा होगी। इस अवसर पर डिप्लोमा अभियंता संघ के अध्यक्ष राजेश जायसवाल, महासचिव दीपक निकुंज, प्रांतीय उपाध्यक्ष सुरजीत गुप्ता, इंजीनियर एसोसिएशन से आर. नागवंशी, जनता यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष जे.पी. पटेल, आर.के. राजपूत, एम.एच. अंसारी, महासंघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद शुक्ला, अभिषेक बोहिदार, बिमलेंद्र साहू, मेरी लिली तिर्की, अनिल बैरागी, शशांक करमहे, खिलेश्वर चन्द्राकर, धर्मेंद्र देवांगन सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

(बालाजी क्लीनिक)
मद्रासी दवाखाना
Reg. No. Cg03026 ISO 9001: 2015 CERTIFIED

बादी एवं खूनी बवासीर, नासूर, भगंदर, फीसर एवं कांच (गुदा) का क्षार सूत्र से, एवं आंतों की बीमारियों जैसे पेट का भारीपन, गैस, कब्ज, पुरुष और स्त्री के गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है।

डॉ. के.एम. राव
एम.एस.(आयु) शल्य
भूतपूर्व प्राध्यापक शल्य विभाग
शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद

समय :- सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से 2, शाम 6 से 7:30
रविवार सुबह 10 से 2, शाम को बंद रहेगा

बिलासपुर रोड, बिलासपुर चौक, अम्बिकापुर मो. 90099-56307

निधन
रामबिलास सिंह

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर के महाप्रबंधक संजय कुमार सिंह के पिता रामबिलास सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। स्व. रामबिलास सिंह अपने पुत्र राजेश सिंह के साथ मध्यप्रदेश भोपाल के छत्रसाल नगर में निवासरत थे।

शनिवार को उनका स्थानीय मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया, जिन्हें मुखाग्नि ज्येष्ठ पुत्र राकेश सिंह ने दी। वे अपने पीछे चार पुत्र एक पुत्री नाती पोते सहित भरापुरा परिवार शोकाकुल छोड़ गए हैं।

बदहाल सड़कों, स्मार्ट मीटर और महंगी चीनी के विरोध में कांग्रेस का चक्काजाम

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। बदहाल सड़कों, स्मार्ट मीटर के नाम पर बढ़े बिजली बिल, चीनी के बढ़ते दाम और अन्य मूलभूत जनसमस्याओं को लेकर शनिवार को लटोरी में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लटोरी के नेतृत्व में आयोजित धरना-प्रदर्शन के बाद चक्काजाम किया गया, जिससे लटोरी-कल्याणपुर मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित रही।

आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आमजन से जुड़े मुद्दों का तत्काल निराकरण किए जाने की मांग की। धरना प्रदर्शन में पूर्व भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े, कांग्रेस जिला प्रभारी द्वितेंद्र मिश्र, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भगवती राजवाड़े, ब्लॉक प्रभारी इम्तियाज जफर, ब्लॉक अध्यक्ष

भाजपा सरकार पर जनहित की अनदेखी का आरोप

कंवल बिहारी सिंह टेकाम तथा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गोवर्धन सिंह मरकाम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला प्रभारी द्वितेंद्र मिश्र ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल की ऐसी कोई उपलब्धि नजर नहीं आ रही है, जिसका आम जनता को सीधा लाभ मिला हो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि किसी को सरकार की कोई उपलब्धि दिखाई देती है तो वह उसे बताएं, उसे इनाम दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों का लाभ आम लोगों की बजाय बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है और गरीब एवं मध्यम वर्ग लगातार परेशानियों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आमजन के अधिकारों और सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को

लेकर सड़क पर उतरती रहेगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि सिंह ने भाजपा की डबल इंजन सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि प्रदेश में सड़क की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खराब सड़कों के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है, जबकि बार-बार मांग और शिकायत के बावजूद लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं।

उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रही है। वहीं चीनी के दाम में बढ़ोतरी का असर आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से पहले ही परेशान आमजन अब रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के बढ़ते दाम से परेशान है। शशि सिंह ने कहा कि यदि सरकार आम जनता की समस्याओं को इसी तरह नजरअंदाज करती रही तो कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और सरकार को जनता की आवाज सुनने के लिए मजबूर किया जाएगा। पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में आमजन मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होने को विवश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें लगातार नजरअंदाज कर रही है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं और लोगों की मांगों का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो कांग्रेस आगामी दिनों में इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने विशेष रूप से लटोरी-कल्याणपुर मार्ग की मरम्मत सहित क्षेत्र की अन्य मूलभूत समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग उठाई। चक्काजाम के कारण मार्ग पर यातायात प्रभावित होने के बाद संबंधित प्रशासनिक स्तर पर बातचीत की गई। आंदोलनकारियों को लटोरी-कल्याणपुर मार्ग की मरम्मत सहित अन्य मांगों को जल्द पूरा किए जाने का लिखित आश्वासन दिया गया। इसके बाद कांग्रेस ने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि आश्वासन के अनुरूप मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी दिनों में आंदोलन को फिर से तेज किया जाएगा।

कालोनियों में स्थायी बिजली कनेक्शन हेतु विधायक को सौंपा स्मरण पत्र

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। नगर पंचायत बिश्रामपुर के बड़ी बसाहट क्षेत्र में स्थायी बिजली कनेक्शन का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। वर्षों से एसईसीएल की विद्युत आपूर्ति पर निर्भर सैकड़ों परिवारों की परेशानी को लेकर बिश्रामपुर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह डीके ने प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी को स्मरण पत्र सौंपकर चुनाव के दौरान किए गए स्थायी बिजली कनेक्शन के संकल्प को पूरा कराने की मांग की है। कांग्रेस मंडल अध्यक्ष ने पत्र में उल्लेख किया है कि नगर पंचायत बिश्रामपुर क्षेत्र की बड़ी बसाहट के सैकड़ों परिवारों के पास आज भी स्वयं का स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है। इन परिवारों की विद्युत व्यवस्था एसईसीएल पर निर्भर है। यही नहीं नगर पंचायत कार्यालय सहित विभिन्न स्थानों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था भी इसी विद्युत व्यवस्था से जुड़ी हुई है। ऐसे में बिजली आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा का सीधा असर आम नागरिकों के साथ पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ता है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण नगरवासियों और एसईसीएल प्रबंधन के बीच कई बार विद्युत आपूर्ति को लेकर तनावपूर्ण स्थिति निर्मित होती रही है। बिजली कब रहेगी और कब बाधित होगी, इसे लेकर लोगों में अनिश्चितता बनी रहती है। कांग्रेस ने इसे सैकड़ों परिवारों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बताते

हुए सीएसईबी से स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की है। विधायक को सौंपे पत्र में उल्लेख है कि विधानसभा व लोकसभा चुनाव तथा नगर पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के समय वांछित क्षेत्रों में सीएसईबी के स्थायी बिजली कनेक्शन दिलाने का संकल्प जनता के समक्ष रखा गया था। इस आश्वासन से क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी थी कि चुनाव के बाद उनकी वर्षों पुरानी बिजली समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। चुनावों में जनता ने भाजपा के प्रत्याशियों को बड़े अंतर से विजयी बनाकर अपना समर्थन दिया, लेकिन करीब तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी संबंधित क्षेत्र में एक भी स्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं लग सका है। इससे क्षेत्रवासियों में निराशा बढ़ती जा रही है। स्मरण पत्र के माध्यम से विधायक का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए कहा गया है कि नागरिकों को आज भी बिजली की अनिश्चितता के बीच जीवन बिताना पड़ रहा है। लगातार बनी रहने वाली इस समस्या के कारण लोगों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है।

कांग्रेसियों ने विधायक से मांग की है कि वे संबंधित विभाग और सीएसईबी से समन्वय कर वांछित क्षेत्रों में स्थायी बिजली कनेक्शन दिलाने की दिशा में ठोस पहल करें, ताकि सैकड़ों परिवारों को वर्षों पुरानी समस्या से स्थायी राहत मिल सके। स्मरण पत्र सौंपने वालों में अनुपम फिलिप, प्रेमजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह डीके, वीरेंद्र मिश्रा और हुपेश प्रजापति उपस्थित रहे।

दो दिन में चोरों ने दिया तीन चोरी की वारदात को अंजाम

एक रात दुकान-मकान तो अगले दिन ठेले को बनाया निशाना

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

चांदनी-बिहारपुर। क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत महूली में दो दिनों के भीतर तीन चोरी की वारदातों ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। पहले दिन एक ही रात में किराना दुकान और मकान को निशाना बनाया गया, जबकि दूसरे दिन किराना दुकान के ठेले का ताला तोड़कर हजारों का सामान पार कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार पहले दिन अज्ञात चोरों ने राज नारायण जायसवाल की किराना दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपये का सामान और नगद चोरी कर लिया। इसी रात गुलाब चंद जायसवाल के मकान का भी ताला तोड़कर चोर सामान लेकर फरार हो गए। वहीं दूसरे दिन प्रवेश जायसवाल के ठेले का ताला तोड़कर हजारों रुपये का सामान चोरी कर लिया गया। लगातार दो दिनों में तीन चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में इससे पहले भी कई चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक सभी मामलों का खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ दिन पहले बकरा टोला निवासी भगवान दास केवट के घर का ताला तोड़कर चोर संदूक ही ले गए थे। संदूक में लाखों रुपये रखे होने की बात सामने आई थी, लेकिन इस मामले में भी अब तक चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लगातार चोरी की घटनाओं और पुराने मामलों का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरी के मामलों का जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन लगातार वारदातों के बीच चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

लिखित आश्वासन के बावजूद कोयला व राखड़ लोड वाहनों के परिवहन से नाराज लोगों ने फिर किया चक्काजाम

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। पिलखा नायब तहसीलदार द्वारा शुक्रवार को बिश्रामपुर-भटगांव मार्ग पर हुए चक्काजाम उपरांत लिखित आश्वासन दिया गया था कि अब सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक कोयला और राखड़ लोड भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। साथ ही दुर्घटना में घायल आटो चालक के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन शनिवार को न तो भारी वाहनों की आवाजाही थमी और न ही पीड़ित परिवार को सहायता मिली। इससे आक्रोशित कालोनीवासियों ने शनिवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे नगर पंचायत कार्यालय बिश्रामपुर के समीप फिर कोयला व राखड़ लोड वाहनों को रोककर चक्काजाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्काजाम के कारण मार्ग के दोनों ओर कोयला और राखड़ लोड वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया था तो उसका पालन क्यों नहीं कराया गया। इसी दौरान यातायात प्रभारी बृजकिशोर पांडेय ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि उन्हें सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहन रोकने संबंधी कोई आदेश नहीं मिला है। इस बयान से आंदोलनकारियों का आक्रोश और बढ़ गया। इधर लटोरी तहसीलदार चंद्रशिला जायसवाल और पिलखा नायब तहसीलदार मीना सिंह को भी आंदोलनकारियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा।

दुर्घटना करने वाले ट्रक मालिक के जिला चिकित्सालय पहुंचने की जानकारी मिलने पर तहसीलदार घायल आटो चालक की पत्नी अनिता को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचीं। वहां वाहन मालिक ने अनिता को 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी और उपचार में हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। वही नायब तहसीलदार मीना सिंह ने बताया कि पीएम राहत योजना के तहत पीड़ित को डेढ़ लाख रुपए दिया जाएगा। उसके बाद चक्काजाम समाप्त हुआ। करीब चार घंटे चले चक्काजाम के बाद आंदोलनकारियों ने प्रशासन को एक और चेतावनी देते हुए कहा कि रविवार से सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही नहीं रोकी गई तो वे अनिश्चितकालीन चक्काजाम करेंगे। फिलहाल मार्ग पर खड़े भारी वाहनों को रात 10 बजे तक नहीं हटने देने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश यादव, इंजी. विनय सिंह, जयप्रकाश यादव, अमरेश प्रसाद, पिंटू यादव सहित अन्य कालोनीवासी मौजूद रहे।

बस्तामुक्त विद्यालय में नो बैग डे पर हुए विभिन्न गतिविधि

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। प्रथम बस्तामुक्त शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रुनियाडीह में कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के मंशानुरूप आज बैगलेस डे पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्था प्रमुख सीमांचल त्रिपाठी ने बताया कि आज एक दिन की प्रधान पाठक श्रीमती एम. टोप्पो के नेतृत्व में विद्यालय में रचनात्मक कार्य अंतर्गत यदि पेड़ बोल सकते तो वह हमसे क्या कहते अंतर्गत निबंध लेखन स्पर्धा कराया गया। जिसमें प्रथम स्थान शांति सिंह, द्वितीय वेद राजवाड़े, तृतीय खुशी सिंह ने प्राप्त किया। चित्रकला में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर संगीता यादव, मनीता राजवाड़े, नगीना यादव रहे। पेपर क्राफ्ट अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां जैसे हवाई जहाज, पानी का जहाज, तितली, गुलाब का फूल, नाग देवता इत्यादि कलाकृतियों का निर्माण किया गया, इसमें क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर मयंक सिंह, पायल राजवाड़े एवं पीयूष ने प्राप्त किया। स्वच्छता अभियान अंतर्गत सुहाना सारथी, सरस्वती राजवाड़े एवं माही देवांगन ने उत्कृष्ट कार्य संपादन किया।

एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत वर्षा राजवाड़े, खुशी सिंह, सानिया यादव, सरस्वती राजवाड़े, दीपक राजवाड़े तथा राहुल राजवाड़े द्वारा उत्कृष्ट कार्य संपादन करने पर, विभिन्न खेल गतिविधियों में राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत शतरंज मुंगेली में पायल राजवाड़े तथा साधना राजवाड़े, तैराकी- बिलासपुर में योगेश सिंह द्वारा सरगुजा संभाग का प्रतिनिधित्व किया। वहीं संभाग स्तरीय योग प्रतियोगिता पत्थलगांव में शांति सिंह, पायल राजवाड़े, संध्या राजवाड़े, खुशी सिंह, वेद राजवाड़े, कैलाश राजवाड़े कुश देवांगन, अमन राजवाड़े, धनेश्वर सारथी, विवेक विश्वकर्मा तथा स्वास्तिक विश्वकर्मा ने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन किया, एथलेटिक्स अंतर्गत लंबीकूद अंबिकापुर में निशा राजवाड़े ने द्वितीय स्थान प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता विश्रामपुर बालिका वर्ग में साधना राजवाड़े, कोमल सिंह, खुशी सिंह, अनीता केवट, वर्षा राजवाड़े, पायल राजवाड़े का चयन हुआ है।वहीं बालक वर्ग में रुद्र प्रताप राजवाड़े, शिवम विश्वकर्मा तथा योगेश सिंह का चयन अंडर 14 बालक वर्ग में किया गया है।शतरंज अंबिकापुर के संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में शिवम विश्वकर्मा, वेद राजवाड़े तथा सुनीता सिंह द्वारा उम्दा खेल प्रदर्शन करने वाले बच्चों को एसएमसी अध्यक्ष श्रीमती कौशिल्या राजवाड़े के मुख्य आतिथ्य, श्रीमती एम. टोप्पो एक दिन की प्रधान पाठक की अध्यक्षता तथा श्रीमती एनवती राजवाड़े तथा रिजवान अंसारी के मुख्य आतिथ्य में बच्चों को कॉपी पेन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

संस्था की एक दिन की प्रधान अध्यापिका श्रीमती एम. टोप्पो ने कहा कि प्रधान पाठक के विद्यालय में उपस्थित रहते हुए भी प्रधान पाठक की भूमिका का निर्वहन करना, अपने आप में गौरवान्वित करने का दिन है। वैसे तो संस्था प्रमुख के नहीं रहने पर विद्यालय का नेतृत्व करती आ रही हूं किंतु उनके रहने पर आज करने का अवसर प्राप्त हुआ, मेरे लिए अद्वतीय दिन है और मैं इसे कभी भूल नहीं सकती।

बिना अनुमति साहब के ऑफिस में प्रवेश वर्जित, सरकारी दफ्तर में आम लोगों की एंट्री पर परमिशन का फरमान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। ब्लॉक मुख्यालय ओड़गी स्थित एसडीओ आर ई एस कार्यालय में चस्पा किए गए तीन अलग-अलग नोटिस इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। कार्यालय की दीवार पर एक नोटिस में साफ शब्दों में लिखा है बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है। दूसरे नोटिस में कार्यालय में बैठकर अपना और अधिकारियों का समय व्यर्थ नहीं करने की अपील की गई है। वहीं तीसरे नोटिस में लिखित अनुमति अथवा सहमति के बिना कार्यालय के नाम से किसी भी प्रकार का विज्ञापन या संदेश प्रकाशित नहीं करने की चेतावनी दी गई है। तीनों नोटिस एक साथ लगाए जाने से कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आमतौर पर सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए तैनात रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सड़क, भवन, निर्माण कार्य, भुगतान, तकनीकी स्वीकृति और विभिन्न शासकीय योजनाओं से जुड़ी समस्याएं लेकर अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। ऐसे में अधिकारी से मिलने के लिए पहले अनुमति की व्यवस्था लागू किए जाने से आम लोगों की पहुंच को लेकर स्थिति अलग नजर आ रही है। नियमों के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रवेश व्यवस्था निर्धारित की जा सकती है। लेकिन आम नागरिकों को अधिकारी से मिलने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य किए जाने की स्थिति में संबंधित विभागीय आदेश और सक्षम अधिकारी की अनुमति का स्पष्ट आधार होना जरूरी है। कार्यालय में लगाए गए नोटिस में किसी शासनादेश, आदेश क्रमांक अथवा दिनांक का उल्लेख दिखाई नहीं देता। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भी सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देता है। वहीं शासन स्तर पर जनसमस्याओं के निराकरण के लिए जनदर्शन और शिकायत निवारण जैसी व्यवस्थाएं संचालित हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर अधिकारी से मिलने की प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी होना जरूरी है। खास बात यह है कि ब्लॉक मुख्यालय के अन्य सरकारी कार्यालयों में इस तरह की सख्त सूचना आम तौर पर नजर नहीं आती। स्थानीय लोगों के अनुसार जनपद पंचायत सीईओ कार्यालय में भी इस तरह का नोटिस नहीं लगाया गया है। ऐसे में एसडीओ आर ई एस कार्यालय में लगाए गए नोटिस ने व्यवस्था को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। यदि विभाग ने अधिकारी से मिलने के लिए पूर्व अनुमति की व्यवस्था लागू की है तो उसका आदेश, प्रक्रिया और निर्धारित समय सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि ग्रामीणों को अनावश्यक परेशानी न हो। सरकारी कार्यालयों में अनुशासन जरूरी है, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें अधिकारी का समय भी बचे और आम जनता की आवाज भी अधिकारी तक आसानी से पहुंचे।

फोटो में चस्पा नोटिस अब ओड़गी की सरकारी व्यवस्था और जनता की पहुंच के बीच खिंची नई प्रशासनिक लकीर की तस्वीर पेश कर रहे हैं।

पूर्वजों के स्मरण में किया गया पौधरोपण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। भाद्रपद अमावस्या पर बेल पौधे का रोपण कर अपने पूर्वजों को स्मरण किया गया।नगर के वरिष्ठजनों ने रेड नदी के समीप न केवल पौधरोपण किया बल्कि उसके सरंक्षण का भी संकल्प दोहराया।सेवानिवृत्त विकास अधिकारी के के शर्मा,अम्बिकापुर के वरिष्ठ प्रबंधक विमलेश पाठक,अधिवक्ता के के मिश्र, व्यवसायी ओमप्रकाश चौबे, एरिया मैनेजर मनोज मिश्र व पत्रकार उपेंद्र दुबे आदि ने आज श्मशान भूमि परिसर में बेल पौधों का रोपण कर उनके रख रखाव का संकल्प लिया।इस मौके पर इस बात पर जोर दिया कि बढ़ते प्रदूषण और जलस्तर में गिरावट जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका अधिक से अधिक पौधे लगाना है। एक पेड़ सिर्फ हवा साफ नहीं करता, बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों

के लिए शुद्ध जल, समृद्ध मिट्टी और एक सुरक्षित वातावरण तैयार करता है। आज लगाया गया एक छोटा सा पौधा कल किसी के लिए छांव और जीवनदायी ऑक्सीजन बनेगा।

मेडिकल कॉलेज में अटैचमेंट के खेल से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर से मलाईदार पदों पर अटैचमेंट का खेल शुरू हो गया है। अटैचमेंट से हटाए गए स्वास्थ्य कर्मी अपनी पहुंच का दुरुपयोग कर फिर से पसंदीदा और मलाईदार पदों पर रोलबैक कर गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर चरमरा गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर अटैचमेंट को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि अटैचमेंट की आड़ में मैदानी स्वास्थ्य कर्मी शहरी क्षेत्रों में जमे पड़े हैं, जिससे

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा की गंभीर स्थिति बनी हुई है। इस गंभीर बहस के बाद जनवरी-फरवरी 2026 में बड़ी कार्रवाई हुई थी। केवल सरगुजा संभाग में ही 432 ऐसे अधिकारी-कर्मचारी चिन्हांकित किए गए थे, जो अपनी मूल पदस्थापना को छोड़कर मलाईदार पदों अथवा पसंदीदा जगहों पर नौकरी कर रहे थे। इसके बाद संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने सभी का अटैचमेंट समाप्त कर उन्हें मूल स्थान पर भेजने के निर्देश दिए थे। सरकार के इस निर्णय के बाद चिकित्सकों से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मियों को वापस अपने मूल पदों पर लौटना पड़ा था।

जरूरत की आड़ में रोलबैक

जानकारी के अनुसार, बेहद आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन ने कुछ इक्के-दुक्के स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरत के मुताबिक अटैचमेंट पर वापस बुलाया था। बस इसी की आड़ में अपने रसूख के दम पर कई अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी सीएमएचओ के मार्फत वापस मलाईदार पदों पर रोलबैक कर गए। इस अटैचमेंट के खेल में भफौली और दरिमा जैसे स्वास्थ्य केंद्र ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट के कारण जहां एक ओर मेडिकल कॉलेज में बिना काम के भीड़ बढ़ गई है, वहीं ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र खाली हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर, सीएचसी दरिमा में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मी आनंद यादव जबरन मेडिकल कॉलेज में जमे हुए हैं, जहां उनकी आवश्यकता ही नहीं है। वहीं उनके मूल पद पर नहीं रहने से क्षेत्र का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि जबरन अटैचमेंट के इस खेल से अस्पताल प्रबंधन भी परेशान और लाचार है तथा इस संबंध में कुछ भी बोलने से बच रहा है।

छात्राओं को मिली सरस्वती साइकिल तो खिले चेहरे

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

लखनपुर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुटपुटरा में निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई तथा उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। साइकिल प्राप्त होने पर छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखते ही बनी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद पंचायत उपाध्यक्ष कामेश्वर राजवाड़े रहे। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने छात्राओं को साइकिल प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि शासन की यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश बारी ने कहा कि साइकिल मिलने से छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा होगी और आवागमन की समस्या कम होने से वे नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश साहू और राजेंद्र जायसवाल ने भी संबोधित किया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत आधार है। बेटियों को शिक्षा के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

शासन की ऐसी योजनाएं बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनके शैक्षणिक भविष्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने छात्राओं से साइकिल का सदुपयोग करते हुए नियमित रूप से विद्यालय आने और मन लगाकर पढ़ाई करने का आह्वान किया।

कुंवरपुर जलाशय में जल संसाधन विभाग का वृक्षारोपण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

लखनपुर। जल संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग द्वारा शनिवार को कुंवरपुर जलाशय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न फलदार पौधों का रोपण किया गया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधे की सुरक्षा और उसकी नियमित देखरेख करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब एक छोटा-सा पौधा सुरक्षित रहकर बड़ा वृक्ष बनता है, तभी उसकी वास्तविक उपयोगिता सामने आती है। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमें शुद्ध वायु, छाया, फल तथा पर्यावरण संतुलन प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधरोपण के साथ-साथ उसकी जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जल संसाधन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों की नियमित देखरेख एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिन जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के नाम से पौधे लगाए गए हैं, उन्हें भी इन पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। जलाशयों एवं सार्वजनिक स्थलों के आसपास अधिक से अधिक पौधरोपण कर उनके संरक्षण की दिशा में सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शशिकला सिंह, उपाध्यक्ष कामेश्वर राजवाड़े, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री साहू, जिला पंचायत सदस्य विजय अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष दिनेश बारी, जिला उपाध्यक्ष दिनेश साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, राजेंद्र जायसवाल, नरेंद्र पांडे, सुरेश साहू, यतेंद्र पांडे, राकेश राजवाड़े सहित जल संसाधन विभाग के एसडीओ दीपक गोयल, इंजीनियर एवं विभागीय कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

रबी 2026-27 के लिए अनुसंधान एवं प्रसार बैठक संपन्न, उन्नत तकनीकों पर हुई चर्चा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत परिक्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, अंबिकापुर में रबी मौसम 2026-27 के लिए अनुसंधान एवं प्रसार बैठक (स्तर-क) का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, अंबिकापुर के सेमिनार हॉल में हुआ। बैठक के प्रथम सत्र की अध्यक्षता संयुक्त संचालक कृषि सरगुजा संभाग के प्रतिनिधि किशन कौशिक ने की तथा सह-अध्यक्ष के रूप में अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय शंकरगढ़ डॉ. जी.पी. पैंकरा उपस्थित रहे। श्री कौशिक ने रबी फसलों में लगने वाले माहू एवं रसचूसक कीट की समस्या के बारे में जानकारी दी। इस दौरान रबी 2025-26 के अनुसंधान परिणामों, खेत प्रदर्शन एवं कृषि/उद्यानिकी गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा आगामी रबी मौसम के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। कृषि विज्ञान केन्द्र अंबिकापुर, सीतापुर तथा बलरामपुर के वैज्ञानिकों ने अपने-अपने कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। द्वितीय सत्र की अध्यक्षता अधिष्ठाता, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय अंबिकापुर डॉ. एस.के. सिन्हा ने की तथा सह-अध्यक्ष के रूप में सहायक संचालक अनुसंधान, परिक्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र डॉ. के.एल. पैंकरा रहे। सत्र में कृषि मौसम विज्ञान, ए.आई.सी.आर.पी. परियोजनाओं में क्षमतावान फसल एवं मक्का फसल, दलहन, तिलहन, मधुमक्खी पालन, उद्यानिकी फसल एवं विभिन्न आई.आर.पी. परियोजनाओं सहित विभिन्न विषयों के रबी 2025-26 के परिणामों एवं रबी 2026-27 की प्रस्तावित अनुसंधान योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

भाजपा विधि प्रकोष्ठ का परिचय सम्मेलन व वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान समारोह संपन्न

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ जिला सरगुजा के तत्वावधान में संकल्प भवन (भाजपा जिला कार्यालय) अंबिकापुर में परिचयात्मक सम्मेलन तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा भारत माता, पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। सम्मेलन के प्रथम सत्र में विधि प्रकोष्ठ के नवनियुक्त एवं सक्रिय अधिवक्ताओं का परिचय सत्र आयोजित हुआ, जिसमें संगठन की मजबूती और विधिक माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में न्याय जगत में दीर्घकालिक एवं उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व विधायक देवेश्वर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता पी.आर. कश्यप, लखन कश्यप, एस.के. पाण्डेय एवं एन.पी. सिंह को शॉल, श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। अपने संस्मरण साझा करते हुए पूर्व विधायक देवेश्वर सिंह ने कहा कि आपातकाल के काले दौर में जब हम विपक्ष में थे, तब कोई खुलकर साथ खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। चारों तरफ भय और दबाव का माहौल था, लेकिन उन संघर्षपूर्ण दिनों में भी हमने बिना डरे सिद्धांतों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कानूनी व वैचारिक लड़ाई लड़ी। आज विधि प्रकोष्ठ की इतनी विशाल टीम को देखकर गर्व की अनुभूति होती है। वरिष्ठ अधिवक्ता पी.आर. कश्यप ने कहा कि आपातकाल में न्यायपालिका और संविधान की मर्यादा को बचाए रखना एक भीषण अग्निपरीक्षा थी। जब साधन सीमित थे और कोई साथ देने वाला नहीं था, तब अधिवक्ताओं ने अकेले दम पर सड़कों से लेकर न्यायालयों तक अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद रखी। भाजपा जिलाध्यक्ष भरत सिंह सिसोदिया ने कहा कि आज से पहले विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उंगलियों पर गिने जाते थे, लेकिन जिला संयोजक जन्मेजय पाण्डेय के नेतृत्व में भाजपा विधि प्रकोष्ठ सरगुजा की विशाल व सशक्त टीम बनी है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधि प्रकोष्ठ द्वारा हर दूसरे और तीसरे शनिवार को संकल्प भवन में लगाए जाने वाले विधिक सहायता शिविर की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। अध्यक्षीय उद्बोधन में जिला संयोजक जन्मेजय पाण्डेय ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अनुभव व आशीर्वाद ही संगठन की वास्तविक पूंजी है। विधि प्रकोष्ठ पूरी ऊर्जा और निष्ठा के साथ आमजन व असहायों को सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क न्याय और कानूनी संरक्षण पहुंचाने के साथ अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रकोष्ठ अग्रणी भूमिका निभाएगा। समारोह को सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो, महापौर मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, विद्यानंद मिश्रा एवं धनंजय मिश्रा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन सह-संयोजक सम्पूर्णान्क गुप्ता ने किया तथा आभार प्रदर्शन पीयूष कुमार त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री विनोद हर्ष, अरुणा सिंह, मधुसूदन शुक्ला, गौरांग सिंह, अशोक दुबे, विवेक सिंह, विनोद दुबे, सुदामा यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण एवं भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

विधायक ने ली विभागीय समीक्षा बैठक, योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर दिया जोर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। स्थानीय सामुदायिक भवन में विधायक भूलन सिंह मरावी की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान विधायक भूलन सिंह ने अधिकारियों से शासन द्वारा चलाए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने, निर्माण कार्यों की प्रगति और लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने और मैदानी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए योजनाओं व कार्यों की सतत निगरानी एवं नियमित समीक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने क्षेत्र की आवश्यकताओं व स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को गति देने की बात कही। समीक्षा बैठक में अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं, प्रगतिरत कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा हुई, जिनके निराकरण पर आपसी समन्वय के माध्यम से जोर दिया गया। विधायक ने सभी विभागों को गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ काम करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को अधिक से अधिक लाभ दिलाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष रेखा राजवाड़े, जनपद अध्यक्ष गुलाब सिंह, उपाध्यक्ष रामप्रताप साहू, जिला पंचायत सदस्य हेमलता राजवाड़े, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन सिंह, देवनगर मंडल अध्यक्ष अनिल साहू, महामंत्री सौभाग्य दुबे, सुमित राज, लाल राजवाड़े, जयप्रकाश उपाध्याय सहित जनपद सदस्यगण तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने किया नवीन मेडिकल कॉलेज गंगापुर और आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत एवं जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव ने नवीन मेडिकल कॉलेज गंगापुर के निर्माण कार्य, लुण्ड्रा विकासखण्ड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं एकलव्य आवासीय विद्यालय सहनपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य, विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षणिक, आवासीय, स्वास्थ्य, भोजन एवं खेलकूद संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने निमार्णाधीन मेडिकल कॉलेज गंगापुर का निरीक्षण कर विद्युत सर्विसेज, गैस पाइप, एचवीएसी (डक्ट), फायर फाइटिंग, फायर अलार्म संबंधित कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे भवन के सिविल कार्य में रुकावट न हो। साथ ही सिविल कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने दिसंबर 2027 तक नवीन मेडिकल कॉलेज के सभी प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यस्थल पर बाल मजदूरों को कार्य में नहीं रखने तथा कार्यस्थल पर सूचना पटल अंकित करने के भी निर्देश दिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लुण्ड्रा के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छात्रावास की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने सीपेज वाली छत की सफाई कराने तथा छात्रावास के पीछे जलभराव वाले स्थान का भराव कर समतलीकरण कराने के निर्देश जनपद पंचायत सीईओ को दिए। उन्होंने कमरों में लगी तिरपाल को हटाकर प्रोफाइल शीट लगाने के निर्देश दिए।

विद्यार्थियों से संवाद कर व्यवस्थाओं की ली जानकारी

कलेक्टर वसंत ने विद्यार्थियों से सहज संवाद करते हुए

विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता, भोजन व्यवस्था, खेलकूद की सुविधाओं, अभिभावकों से संपर्क तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एक छात्रा की आंखों के उपचार की आवश्यकता की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने शंकर नेत्रालय, हैदराबाद में उपचार के लिए आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों के लिए खेल सामग्री एवं किक बॉक्सिंग सामग्री उपलब्ध कराने तथा कंप्यूटर शिक्षा के लिए डीएमएफ मद से शिक्षक की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

एकलव्य विद्यालय की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

कलेक्टर ने एकलव्य आवासीय विद्यालय सहनपुर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक एवं आवासीय व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर दिया। उन्होंने साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकारों की पुस्तकों को लाइब्रेरी में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ खेल एवं संगीत जैसी रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कलेक्टर ने रैगिंग एवं किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को परेशान किए जाने की घटनाओं पर प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भोजन व्यवस्था का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और निमार्णाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने को कहा। विद्यार्थियों की मांग पर विद्यालय में सोलर गीजर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अविनाश मिश्रा, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक आर.सी. आर्य, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, एसडीएम विनय सोनी, तहसीलदार तुषार सहित विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सम्पादकीय

पायलटों पर सख्ती सुरक्षा की जरूरत

हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में बैठे यात्रियों की जिंदगी पायलट के हाथ में होती है। ऐसे में पायलट का नशे में होना या नशीले पदार्थों के असर में उड़ान भरना केवल अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डालने वाली गंभीर चूक है। फुकेट-दिल्ली उड़ान की घटना ने विमानन सुरक्षा के इसी कमजोर पक्ष को सामने ला दिया है। अब सभी एयरलाइनों के पायलटों की ड्रग जांच कराने का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है कि कॉकपिट तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति पूरी तरह फिट और नशामुक्त हो। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की ए320 उड़ान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गई। विमान में 137 यात्री और आठ चालक दल के सदस्य थे। घटना में 20 यात्री और चार चालक दल के सदस्य घायल हुए तथा 17 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। विमान हादसा जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार अचानक और थोड़े समय के लिए तीनों हाइड्रोलिक प्रणालियों में खराबी सामने आई। इसी रिपोर्ट में विमान के कप्तान की मनो-सक्रिय पदार्थों की जांच का परिणाम 'नॉन-नेगेटिव' पाए जाने का भी उल्लेख है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच एजेंसी ने पायलट के ड्रग सेवन को विमान की ऊंचाई में आई गिरावट का कारण नहीं बताया है। फिर भी उसने मनो-सक्रिय पदार्थ के सेवन की पुष्टि को गंभीर चिंता माना और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की सिफारिश की। इस घटना के बाद डीजीसीए ने सभी भारतीय एयरलाइनों को अपने सभी पायलटों की एक बार ड्रग जांच कराने का निर्देश दिया है। देश में करीब 14 हजार पायलट हैं और अगले वर्ष जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी की जानी है। एयर इंडिया समूह पहले ही अपने करीब 5 हजार पायलटों की स्वैच्छिक एकमुश्त जांच शुरू कर चुका था। यह पहल जरूरी है, लेकिन असली परीक्षा इस बात की होगी कि जांच केवल घटना के बाद उठाया गया कदम न रह जाए, बल्कि विमानन सुरक्षा व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बने। मौजूदा नियमों के तहत हर वर्ष 10 प्रतिशत पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की यादृच्छिक जांच अनिवार्य है। सुरक्षा से जुड़े अन्य कर्मचारी भी इसके दायरे में आते हैं। अब सभी पायलटों की साल में एक बार जांच कराने की दिशा में नियमों को और सख्त करने की तैयारी है। मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारी के मूत्र के नमूने को दो अलग कंटेनरों में सुरक्षित रखा जाता है। पहले नमूने की तत्काल जांच होती है। यदि परिणाम 'नॉन-नेगेटिव' आता है तो पायलट को तुरंत उड़ान ड्यूटी से हटा दिया जाता है। दूसरे नमूने की अधिक सक्षम प्रयोगशाला में पुष्टि जांच होती है। यह जरूरी है, क्योंकि कुछ दवाओं या तकनीकी कारणों से शुरुआती जांच में गलत सकारात्मक परिणाम आ सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति के करियर पर अंतिम फैसला पुष्टि जांच के बाद ही होना चाहिए। पुष्टि होने पर पहली बार कर्मचारी को विशेषज्ञ चिकित्सक, परामर्शदाता या नशामुक्ति केंद्र के पुनर्वास कार्यक्रम में भेजने का प्रावधान है। दोबारा उड़ान पर लौटने के लिए नकारात्मक जांच और फिटनेस प्रमाणपत्र जरूरी है। सकारात्मक पाए जाने पर लाइसेंस तीन वर्ष के लिए निलंबित और तीसरी बार पुष्टि होने पर रद्द किया जा सकता है। कुल मिलाकर कॉकपिट में नशे की एक भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ड्रग टेस्ट को कागजी खानापूर्ति नहीं, उड़ान से पहले सुरक्षा की अनिवार्य दीवार बनाना होगा। आसमान में छोटी-सी चूक की कीमत बहुत बड़ी होती है।

सम्मेलन

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

ब्रिक्स के जरिए भारत होगा लाभान्वित

> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और निरंतरता' है। 'मानवता प्रथम' के दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ आयोजित यह सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है, जब वैश्विक व्यवस्था गहरे ध्रुवीकरण, आर्थिक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखलाओं के व्यवधान से जूझ रही है। ऐसे में 11 पूर्णकालिक सदस्यों और 10 सहयोगी देशों के इस विशाल मंच के माध्यम से भारत न केवल विकासशील राष्ट्रों (ग्लोबल साउथ) की प्राथमिकताओं को दिशा दे रहा है, बल्कि खुद को एक निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है।

इन दिनों पूरी दुनिया की निगाहें 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की ओर लगी हुई हैं। यह वैश्विक संगठन अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मनाते हुए अपने विस्तारित 'ब्रिक्स प्लस' के स्वरूप में एक मंच पर एकत्रित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और निरंतरता' है। 'मानवता प्रथम' के दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ आयोजित यह सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है, जब वैश्विक व्यवस्था गहरे ध्रुवीकरण, आर्थिक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखलाओं के व्यवधान से जूझ रही है।

ऐसे में 11 पूर्णकालिक सदस्यों और 10 सहयोगी देशों के इस विशाल मंच के माध्यम से भारत न केवल विकासशील राष्ट्रों (ग्लोबल साउथ) की प्राथमिकताओं को दिशा दे रहा है, बल्कि खुद को एक निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। खास बात यह भी है कि ब्रिक्स सम्मेलन से भारत के आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर लाभान्वित होने की संभावनाएं स्पष्ट रूप से उभर कर दिखाई दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में अपनी शुरुआत के बाद से ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक शासन, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों-जैसे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक मजबूत आवाज देना था। यह महत्वपूर्ण है कि विस्तार के बाद ब्रिक्स अब 11 पूर्णकालिक सदस्यों का एक अत्यधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली आर्थिक ब्लॉक बन चुका है। इसमें पांच मूल देशों के साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और इंडोनेशिया शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही 10 अन्य राष्ट्रों को सहयोगी देश का दर्जा दिया गया है। इस समय ब्रिक्स का जनसांख्यिकीय एवं आर्थिक प्रभाव अभूतपूर्व है। यह संगठन वैश्विक जनसंख्या के करीब 49.5 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर ब्रिक्स का वैश्विक जीडीपी में योगदान करीब 40 प्रतिशत हो चुका है। यदि हम 18वें शिखर सम्मेलन के प्रमुख एजेंडे को देखें तो पाते हैं कि इस शिखर सम्मेलन के लिए भारत ने जिन प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है, वे न केवल ब्रिक्स सदस्यों बल्कि संपूर्ण विकासशील जगत के आर्थिक और सामाजिक हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व से उत्पन्न होने वाले मुद्रा जोखिमों और विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए स्थानीय मुद्राओं मसलन रुपया, रूबल, दिरहम में व्यापार को बढ़ावा देना प्रमुख एजेंडा है। भारत पहले ही यूएई के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत कर चुका है। इस व्यवस्था के विस्तार से सीमा पार भुगतानों में लगने वाली लागत घटेगी और छोटे व मध्यम उद्योगों के लिए व्यापार करना सुगम होगा। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स देशों के बीच एक मजबूत, लचीली और पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। इसके साथ ही न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के वित्तीय दायरे को बढ़ाकर हरित ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित

करना है। भारत अपने 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' (डीपीआई)-विशेष रूप से यूपीआई को ब्रिक्स देशों के बीच सीमा पार भुगतान और वित्तीय समावेशन के लिए एक साझा ढांचे के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के सुरक्षित, नैतिक और उत्तरदायी उपयोग के लिए नीतियां तैयार करना सम्मेलन की मुख्य प्राथमिकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि यह सम्मेलन भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। रूबिक्स डेटा साइंसेस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025-26 में ब्रिक्स देशों के साथ भारत का कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 416 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। भारत का कुल आयात 320 अरब डॉलर का है, यह आयात मुख्य रूप से ऊर्जा (कच्चा तेल, गैस) और विनिर्माण इनपुट (इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी) पर केंद्रित है। ब्रिक्स देशों को भारत का कुल निर्यात लगभग 96 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है। यद्यपि ब्रिक्स देशों के साथ भारत के व्यापार की मात्रा बढ़ी है, लेकिन भारत के लिए 224 अरब डॉलर का भारी-भरकम व्यापार घाटा एक प्रमुख नीतिगत चुनौती बना हुआ है। अकेले चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के करीब है। रूस से भारी मात्रा में रियायती दर पर कच्चे तेल के आयात के कारण रूस के साथ घाटा 55 अरब डॉलर पहुंच चुका है। निश्चित रूप से ब्रिक्स देशों के साथ भारत के व्यापार घाटे की चुनौतियों के बीच इस सम्मेलन से भारत को बहुआयामी आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। उद्योग मंडल एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार, 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में होने वाले रणनीतिक आर्थिक समझौतों के बल पर ब्रिक्स देशों को भारत का निर्यात साल 2030 तक दोगुना होकर 200 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से भारत से निर्यात बढ़ने के साथ-साथ भारत में निवेश और पर्यटन की नई संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। जहां इस संगठन के कई सदस्य देश अलग-अलग आर्थिक दबावों का सामना कर रहे हैं, वहीं भारत की स्थिति इस समूह में बेहद मजबूत है। भारत चालू वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल से जून की तिमाही में 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वैश्विक कंपनियाँ आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों को कम करने के लिए 'चीन+1' रणनीति अपना रही हैं। भारत 'मेक इन इंडिया' और 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (पीएलआई) योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बनकर उभर रहा है। भारत की विशाल और युवा कार्यशील आबादी न केवल घरेलू उपभोग को गति दे रही है, बल्कि नवाचार, आईटी सेवाओं और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी ब्रिक्स देशों का नेतृत्व कर रही है। भारत अब केवल कच्चे माल का निर्यातक नहीं रहा, अपितु फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेवाओं के क्षेत्र में भारतीय उत्पाद ब्रिक्स प्लस के नए बाजारों में अपनी गहरी पैठ बना रहे हैं। यह भारत के लिए महज एक औपचारिक कूटनीतिक आयोजन नहीं होगा, बल्कि यह भारत के वैश्विक कद को पुनर्परिभाषित करने वाला शिखर सम्मेलन सिद्ध होगा। उम्मीद करें कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत ब्रिक्स को ऐसे आर्थिक सुधारवादी मंच के रूप में आगे बढ़ाने में कामयाब होगा, जिसका मूल ध्यान आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, नवाचार और सतत विकास पर केंद्रित हो। उम्मीद करें कि इस सम्मेलन से ब्रिक्स देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ेगा, व्यापार घाटा घटेगा और भारत 21वीं सदी की बहुध्रुवीय दुनिया में एक संतुलनकारी आर्थिक शक्ति के रूप में भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मंथन

रोहित माहेश्वरी

छात्रों को सुरक्षित व सस्ता आवास साझा जिम्मेदारी

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बीती 6 सितंबर को हुए दर्दनाक हादसे में लड़कों के हॉस्टल पीजी के रूप में इस्तेमाल हो रही एक पांच मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस भीषण हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में यह कोई पहला मौका नहीं है, जब कोई ऐसा हादसा हुआ हो। हाल ही में मालवीय नगर के एक 'अवैध, संकरे कथित होटल में अग्निकांड हुआ, जिसमें 22 जिंदगियां भस्म होकर राख बन गईं। कभी राजेन्द्र नगर में बारिश का पानी भर जाता है, उसमें करंट भी प्रवाहित होने लगता है, नतीजतन आधा दर्जन युवा छात्र अचानक लाश बन जाते हैं। कभी लक्ष्मी नगर में हादसा हुआ और फिर युवा जिंदगियों पर विराम लग गया। इसी जुलाई में ही रोहिणी में इमारत गिरी, साकेत और करोल बाग में हादसे हुए। मुस्तफाबाद में 11 मौतें इससे पहले हो चुकी थीं। ये हादसे, मौतें नहीं, बल्कि हत्याएं हैं, क्योंकि बचने के बंदोबस्त 'शून्य' थे। इन तमाम इमारतों में एक तथ्य साझा है कि सभी 'अवैध थीं। न अग्निशमन विभाग का एनओसी, न नगर निगम का एनओसी, स्वीकृत मंजिलों से अधिक मंजिलों का निर्माण और कई इमारतें तो सालों पुरानी थीं, जिनका रखरखाव भी नहीं किया गया था। सत्य निकेतन वाली इमारत भी 36 साल पुरानी बताई गई है। उस पर विभाग ने सील लगा दी थी, लेकिन फिर न जाने कैसे, वह सील भी खुल गई और यह हत्याकांड हो गया। इस इमारत की तीन मंजिलें 'अवैध' थीं, क्योंकि उसे भूतल और पहली मंजिल बनाने की ही अनुमति दी गई थी, लेकिन भूतल के ऊपर भी चार मंजिलों का निर्माण कर लिया गया। सत्य निकेतन में कई निजी इमारतों को पीजी के तौर पर बदला गया है और ज्यादातर पीजी के बाहर पीजी का बोर्ड भी नहीं लगा है।

सवाल है- क्या इस इमारत को बड़ी संख्या में छात्रों के रहने वाले पीजी के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति थी? क्या इमारत में रहने वालों की संख्या के हिसाब से सीढ़ियां, निकासी के रास्ते और दूसरी जरूरी सुविधाएं पर्याप्त थीं? अगर इलाके में पहले से ऐसी समस्याएं थीं, तो एमसीडी को पता क्यों नहीं चला? यह सवाल हादसे के बाद सबसे गंभीर सवालों में से एक बन गया है। समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कई वीडियोज में वहां रहने वाले स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं इस इलाके में पहले भी बिल्डिंग गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि इस इलाके में बड़ी संख्या में रिहायशी इमारतों को पीजी में बदलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यानी यहां एक अहम सवाल खड़ा होता है। अगर इलाके में बड़ी संख्या में पुराने मकानों को बहुमंजिला पीजी में बदला जा रहा था और स्थानीय लोग इमारतों की हालत को लेकर सवाल उठा रहे थे, तो क्या एमसीडी ने ऐसे इलाकों की इमारतों का व्यवस्थित सुरक्षा सर्वे किया था? क्या इस इमारत को पीजी में बदलने से पहले एमसीडी को बताया गया था। और अगर निर्माण नियमों का उल्लंघन हो रहा था, तो उसे समय रहते क्यों नहीं रोका गया? कहा जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हॉस्टल में सिर्फ 9,000 बेड हैं। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को कहीं और रहने की जगह ढूंढनी पड़ती है। और यह सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की समस्या नहीं है। दशकों से, दिल्ली ने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, ऑफिस और रोजगार जमा किए हैं, लेकिन उनके आस-पास कोई सस्ता किराए का घर जैसा इकोसिस्टम नहीं बनाया है। मार्केट ने स्वाभाविक रूप से इस खालीपन को भर दिया। इस तरह आम रिहायशी इलाके बड़े इनफॉर्मल स्टूडेंट शहर बन गए, मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर, विजय नगर, कमला नगर, सत्य निकेतन, बेर सराय, कटवारिया सराय, जिया सराय, मुनिरका और लक्ष्मी नगर, वगैरह। अब सवाल यह नहीं है कि दिल्ली में छात्रों के लिए असुरक्षित आवास हैं या नहीं। हमें पता है कि हैं। सवाल यह है कि शहर इस संकट को एक-एक इमारत और एक-एक मौत के बाद ही क्यों पहचानता है, बजाय यह स्वीकार करने के कि छात्र आवास भी शहरी योजना की जिम्मेदारी है। और शायद सबसे असहज सवाल सबसे आसान है: दिल्ली में नियम अक्सर एंबुलेंस पहुंचने के बाद ही क्यों आते हैं? जब किसी शहर की अर्थव्यवस्था में ये युवा योगदान करते हैं तो उनके लिए सुरक्षित और किफायती आवास की व्यवस्था को केवल निजी समस्या मान लेना उचित नहीं लगता। दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों को यह सोचना होगा कि राजधानी में आने वाले विद्यार्थियों के लिए सस्ती, सुरक्षित और नियमन के अधीन छात्र आवास व्यवस्था क्यों नहीं विकसित की जा सकती?

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जीवन ऊर्जा पर करें मन को केंद्रित

बुद्धिमान व्यक्ति इस ब्रह्मांड, इस संसार से परे चले जाते हैं और अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कैसे? वस्तुतः हमारे भीतर कुछ ऐसा होता है, जो कभी नहीं मरता, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। इस बारे में प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से सोचता है। अगर आप देखें तो छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं और स्थितियां भी बदल रही हैं, लेकिन कई बार आप महसूस

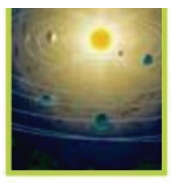

संकलित

दर्शन

करते हैं कि आप नहीं बदल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं- मैं तो बूढ़ा हुआ ही नहीं/हुई ही नहीं। भीतर से आपको महसूस होता है कि सिर्फ समय बीता है, आपमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह सच भी है, क्योंकि आपके भीतर एक ऐसा अंश है, जो न तो बदलता है और न ही मरता है। यही एक दूसरी दुनिया है, जहां अमरत्व है। मृत्युलोक वह है, जहां सब कुछ बदल जाता है। मृत्यु का अर्थ है परिवर्तन या क्षय। आप इस नाशवान संसार से अमरत्व, अपरिवर्तनशील संसार, शाश्वत-आत्मा की ओर मुड़ जाते हैं, जो आपके भीतर है। आपके मन के पीछे है। आत्मा वह नहीं है, जिसे आप देख सकें, बल्कि वह है, जिसे आप अपने भीतर महसूस करते हैं। यह प्राणों का प्राण है। जब प्राण उच्च स्तर में होता है, तब आप हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकते हैं। आप अपनी दैनिक गतिविधियों में प्राण ऊर्जा को खर्च करते हैं। यदि आप प्राण की कमी को पूरा किए बिना प्राण को खर्च करते रहते हैं, तब आपको अवसाद घेर लेता है। जीवन विरोधी चिह्न शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं और सौंदर्य नष्ट होने लगता है। अपने प्राण, अपने श्वास का निरीक्षण करें।

आखिर कर्म ही महान

एक बार बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के यहां गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म

संकलित

प्रेरणा

होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछाः कहां चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूंगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है। प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया, उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूं कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है।

सटाका

आज की पाती

मिट्टी बचेगी, तभी खेती बचेगी

भारतीय कृषि अब एक नए युग की ओर अग्रसर है, जहां विकास का आकलन करने के लिए केवल वृद्धि ही एकमात्र मापदंड नहीं रह गया है। मिट्टी की घटती उर्वरता, भूजल की कमी, जैव विविधता का क्षय, जलवायु परिवर्तनशीलता और बढ़ती खेती लागत के कारण किसान और कृषि क्षेत्र पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस संदर्भ में पुनर्योजी कृषि एक आशाजनक मार्ग है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो न केवल वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगा, बल्कि वास्तव में मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता, जल प्रणालियों और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को बेहतर बनाकर कृषि उत्पादकता को बनाए रखेगा। मुख्य बात पुनर्योजी कृषि पर ध्यान केंद्रित करना और कृषि के पारिस्थितिक स्तंभों को पुनर्स्थापित करना है। अगर मिट्टी बचेगी, तो ही खेती बचेगी। - कृष्णा भारद्वाज, भिवानी

ट्रेंड

रणनीतिक साझेदारी

भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर हमने व्यापार, निवेश, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, टैलेंट मोबिलिटी और अन्य क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया।
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

बीजेपी की बेचैनी

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से पीडीए समाज के लोगों पर ज्यादतियां भी बढ़ रही हैं। हापुड़ जिले के बदनौली गांव में दलित युवक दीपक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई।
- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

सीआईडी एडीजी

सीआईडी के एडीजी पर कोयला चोरी जैसे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि यही एडीजी उस इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य भी थे, जिसका संबंध जेपीएससी के उसी घोटाले से है जिसकी जांच अब सीआईडी ही कर रही है।
- बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम, झारखंड

ईस्ट ज़ोन को बधाई

ईशान किशन की कप्तानी में इतने सालों बाद दिलीप ट्रॉफी जीतने पर ईस्ट ज़ोन को बधाई... वे पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहे... पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए बंगाल के खिलाड़ियों और टीम के बाकी सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई।
-सौरव गांगुली, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी

सड़क की समस्या और तथाकथित समाजसेवी!

मनोज कुमार सिंह

भई जो अंबिकापुर कभी स्वच्छता के तमगे के आभूषण से सुशोभित होता था जैसे ऐश्वर्या राय के कान में बाली। लेकिन आज उसी अंबिकापुर की वही सड़के ओमपुरी का गाल बन गई है?

लेकिन यह सब एकाएक नहीं हुआ, वर्तमान की कुव्यवस्था के लिए अतीत की भ्रष्ट व्यवस्था भी उतनी जिम्मेदार है, खैर इसकी विवेचना काफी वृहद हो सकती है और यह शीर्षक का विषय भी यह नहीं है।

आज अंबिकापुर के सड़को पर जितने गड्ढे नहीं होगे उससे कही अधिक उद्भिज (जमीन चीर कर) और स्वंयभू समाजसेवी और संस्थाए, जनहितकारी और लोकहित परोपकार का चोला पहन समाज के रंगमंच पर अभिनय कर रही है। ऐसा इसलिए की ऐसे लोगो ने कभी असंख्य गड्ढो से युक्त अंबिकापुर की सड़को के किसी एक गड्ढे को भरने के लिए समाज सेवा के नाम पर एक मुठ्ठी रेता या कंकड़ भी डाला होगा? लेकिन आज देखिए इनका समर्पण देख कर लगता है, बाज को अपना मांस खिला कर कबूतर की जान बचाने वाले राजा शिवी और वृत्रासुर के वध के लिए अपनी अस्थियां दान करने वाले ऋषि दधिचि यही है?

सड़क के गड्ढो में भरे जल से स्नान कर ये स्वप्रेरित और तथाकथित समाजसेवी समाज के समक्ष क्या मिसाल पेश करना चाहते है? क्या इन लोगो ने सड़क की सुरक्षा के लिए कभी अंबिकापुर मे जनजागृति का संचार किया?

मुद्दो का निर्माण, मुद्दो की निरंतर खोज और मुद्दो का व्यापार ऐसे लोगो की समाजसेवा की आधारभूत संरचना है। ऐसे लोग समस्याओं के शव पर व्यक्तिगत प्रसिद्धि का आहार ग्रहण करने वाले सामाजिक गिद्ध है। सड़क समस्या पर प्रसिद्धि की क्षुधा को तृप्त करने वाले ऐसे लोग जब समस्याओं को देखते है तो यकीन जाने इनकी प्रसिद्धि की जठराग्नि मन मे यही कहती होगी, कबहु ना मिली भरि उदर आहारा।

आजु दीन्ह विधि एकहि बारा।।

लेकिन इन लोगो का दोष भी इतना नहीं है जितना अगत और विगत शासन का भी है।

जनता फेसबुक व इंस्टाग्राम में ही जीवित सी और धरातल पर निष्प्राण सी प्रतीत होती है।

मै ऐसे पचासो दुकानदारो और लोगो को भी जानता हूं जो प्रतिदिन टूल्लू पंप चालू कर घर के सामने की सड़क को आधे घंटे तक पानी से धोते है, जिससे सड़क की आयु उसी तरह कम होती है जैसे एड्स से मनुष्य का जीवन?

अब तो हर दिन सरकार भी कह रही बस बारिश खत्म होने का इंतजार करे अच्छी सड़के देगे अतः विश्वास भी करना होगा। लेकिन इससे भी अधिक समेकित जन चेतना की आवश्यकता भी है।

यकीन जानिए सड़क समस्या पर ऐसे तथाकथित समासेवी और माइक धारियों के झुंड को देखकर लगता है, जैसे ऊंट के विवाह में गधे गाना गा रहे है।

लेकिन राजमार्ग से लेकर राष्ट्रीय जीवन तक के मार्ग के प्रगति के लिए जन उत्तरदायित्व और चेतना की महती आवश्यकता है। ऐसा न होने पर जनतंत्र में जनता की वही स्थिति होगी जो बत्तीस दांतो के मध्य जीभ की होती है।

डीआईएलआरएमपी 3.0 के दिशा-निर्देश लॉन्च, शिवराज ने किया शुभारंभ

एकीकृत, जीआईएस आधारित 'लैंड स्टैक' किया जाएगा विकसित, हर भू-खंड को मिलेगा 14 अंकों वाला भू-आधार

भूमि किसानों के गौरव और पीढ़ियों की पहचान का प्रतीक

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) 3.0 के परिचालन दिशानिर्देशों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राज्यों के राजस्व मंत्रियों, प्रधान सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। 2026-2031 के लिए 565.50 करोड़ के बजटीय प्रावधान के साथ एकीकृत, जीआईएस-आधारित 'लैंड स्टैक' विकसित किया जाएगा। देश के प्रत्येक भू-खंड को 14 अंकों वाला यूनिवर्सल लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर भू-आधार प्रदान किया जाएगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि डीआईएलआरएमपी 3.0 ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन को आसान बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा कि भारत में भूमि का संबंध भावनात्मक और पारिवारिक पहचान से गहराई से जुड़ा है, इसलिए भूमि से जुड़े सटीक और आसानी से उपलब्ध दस्तावेज अहम हैं।

99.90% अभिलेखों का डिजिटलीकरण पूरा हो गया

चौहान ने कहा कि डीआईएलआरएमपी के पिछले चरणों में 99.90 फीसदी अधिकार अभिलेख और 97 फीसदी कैडस्ट्रल मैप्स का डिजिटलीकरण पूरा किया जा चुका है। 99 फीसदी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण भी पूरा हो चुका है। अब पूरी प्रणाली के एकीकरण की दिशा में काम होगा।

सभी जानकारी एक साथ होंगी

इसमें जियो-रेफरेंस्ड कैडस्ट्रल मैप, अधिकारों के रिकॉर्ड, संपत्ति पंजीकरण और संबंधित अदालती मामलों जैसी भूमि से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से एक साथ लाया जाएगा।

75 सब-रजिस्ट्रार कार्यालय बनेंगे आधुनिक पंजीकरण सेवा केंद्र

ज्यादा भीड़ वाले 75 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक पंजीकरण सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इन केंद्रों में डिजिटल कतार प्रबंधन और नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सीधे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा

राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाकर सीधे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। लंबित मामलों की संख्या कम करना और म्यूटेशन से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी लाना है।

शहरी भूमि रिकॉर्ड के लिए 'नक्शा' को मिलेगी गति

अर्बन लैंड मैपिंग (नक्शा) पायलट प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। इसके तहत सटीक और जीआईएस आधारित शहरी भूमि रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे तथा अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों की पहचान और रिकॉर्ड प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्रीय वित्तपोषण

डीआईएलआरएमपी 3.0 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 फीसदी केंद्रीय वित्तपोषण के साथ चरणबद्ध और प्रदर्शन आधारित व्यवस्था के तहत लागू किया जाएगा। कार्यक्रम का वित्तीय प्रबंधन सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

खबर संक्षेप

शाह ने डॉ. भागवत को शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आरएसएस के प्रमुख मोहन

भागवत को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। शाह ने कहा कि संघ प्रचारक से लेकर सरसंघचालक तक का उनका सफर राष्ट्र सेवा, सामाजिक सद्भाव और भारतीय संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के प्रति समर्पण का एक बेमिसाल उदाहरण है।

फरार पीजी संचालक त्यागी ने किया आत्मसमर्पण

नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने के मामले में फरार आरोपी

और पीजी संचालक शुभम त्यागी ने शुक्रवार को पटियाला हाउस अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने इमारत ढहने की परिस्थितियों के बारे में पूछताछ और जांच के लिए त्यागी को 2 दिन के लिए हिरासत में देने की मांग की है।

अलायंस एयर का विमान आपात स्थिति में उतरा

नई दिल्ली। अलायंस एयर का विमान इंजन में खराबी आने के बाद शुक्रवार अपराह्न आपात

स्थिति में दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। विमान में करीब 40 लोग सवार थे। विमान सुरक्षित रूप से उतरा। एयरलाइन कंपनी प्रयागराज से राष्ट्रीय राजधानी के लिए एटीआर 72-600 विमान से उड़ान संख्या 9आई 698 का संचालन कर रही थी। यह दो इंजन वाला विमान है।

कैफे के बाहर 15 राउंड फायरिंग, 2 घायल

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कम्युनिटी सेंटर के पास एक कैफे के बाहर स्कूटर

सवार 2नकाबपोश लोगों ने कथित तौर पर गोलीबारी कर दी। इसमें दो लोग घायल हुए। हमलावरों ने करीब 15 गोलियां चलाईं और दोनों को गोली लगी। घायल मोहम्मद इरशाद ने बताया वह और दूसरा पीड़ित रात करीब डेढ़ बजे कैफे से बाहर निकले थे, तभी स्कूटर आए।

नांदेड़ में 9 लोगों की मौत प्रधानमंत्री ने शोक जताया

नांदेड़। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुवार को भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3लोग

गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा नांदेड़-भोकर हाईवे पर वाकद गांव के पास सीताखंडी इलाके में हुआ। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हादसे पर प्रधानमंत्री ने शोक जताया है।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में सीतारमण ने कांग्रेस पर कसा तंज

'नाराज फूफा' देश की क्षमताओं पर संदेह का कोई मौका नहीं छोड़ रहे

कुछ लोग जनसांख्यिकीय लाभांश को हमेशा निराशा भरी नजरों से देख रहे

देश डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में अव्वल

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की तेज वृद्धि और युवा शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत वास्तविक समय में अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का अनुभव कर रहा है। देश डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में विश्व में अग्रणी है। यूपीआई के जरिए अरबों के लेनदेन हो रहे हैं। भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने विरोधी दलों पर भी करारा तंज कसा।

उन्होंने संशयवादियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जनसांख्यिकीय लाभांश को सदा निराशा भरी नजरों से देखते हैं। प्रधानमंत्री के शब्द 'नाराज फूफाजी' का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग भारत की आगे बढ़ने की गति और युवाओं की क्षमताओं पर संदेह करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे टेलीविजन स्टूडियो में बहस करते हुए समय बिताते हैं। उनका सवाल होता है कि क्या जनसांख्यिकीय लाभांश हाथ से निकल गया है या बोझ बन गया है।

भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत

निर्मला सीतारमण

सीतारमण ने इस सोच को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह जनसांख्यिकीय लाभांश भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा तय कर रहा है। हमें इस प्रगति का उत्सव मनाना चाहिए। नकारात्मक सोच वाले लोगों की तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। यह देश के भविष्य के लिए एक मजबूत आधार है।

एक संघीय उद्योग मंच बनाने पर जोर दिया

सीतारमण ने एक संघीय उद्योग मंच बनाने पर जोर दिया। यह मंच व्यापक भारतीय प्रौद्योगिकी परिवेश को एक साथ लाएगा। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को थोक और खुदरा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पायलट को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। यह कदम डिजिटल वित्तीय प्रणाली को मजबूत करेगा। यह नवाचार को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

भाजपा प्रवक्ता पात्रा बोले

भारत की प्रगति नहीं पचा पा रहा विपक्ष, नकारात्मक माहौल बना रहा

भाजपा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर 'नकारात्मक माहौल' बनाने का आरोप लगाया और कहा कि देश जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, विपक्षी दल भारत की इस प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। भाजपा ने कहा कि जहां 2011-12 में कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के दौरान ब्रिक्स के भीतर भारत अपनी स्थिति खोता हुआ दिख रहा था, वहीं आज सभी ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में मौजूद हैं।

ब्रिक्स पर कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़े, एक ने इसे विकासशील देशों के लिए अहम मंच बताया

गणेश पूजा में शराब की बिक्री

रोक लगाने से भड़का हाईकोर्ट 10 दिन में तो बीमार हो जाएंगे

एजेंसी ⏭ मुंबई

महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम रहती है। 10 दिन तक चलने वाले इस पूजा के दौरान पुणे के जिला प्रशासन ने शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। जब यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो जज ने जिला प्रशासन के इस फैसले की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि सिर्फ एक जिले को ही क्यों चुना गया, जबकि मुंबई सहित महाराष्ट्र के किसी भी जिले में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को यह आदेश वापस ले लेना चाहिए वरना कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। जिला प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ होटल मालिकों और शराब की दुकान के मालिकों के संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर

की थी। चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने कहा कि जिन्हें शराब बेचने का लाइसेंस प्राप्त है उन्हें 10 दिन तक अपना कारोबार करने से रोकने के लिए कहना पूरी तरह से मनमाना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी पाबंदी से शराब की लत वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। चीफ जस्टिस त्रिपाठी ने मजाकिया लहजे में कहा,अगर उन्हें 10 दिनों तक शराब नहीं मिली तो वे अस्पतालों में भर जाएंगे।

सिर्फ एक जिले में क्यों बैन?

पुणे कलेक्टर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 14 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश उत्सव के दौरान बिक्री पर रोक लगाई गई थी। बेंच ने कहा कि सिर्फ पुणे को चुनने के पीछे क्या तर्क है? हम ऐसी प्रथा की निंदा करते हैं। आप पूरे राज्य में से सिर्फ एक जिला चुन रहे हैं।

चिदंबरम ने कहा- इससे क्या मिला? थरूर ने गिना दिए भारत का मिलन वाल फायदे

भूमिका व कूटनीतिक ताकत बताई, सम्मेलन की मेजबानी देश के लिए गर्व की बात

ब्रिक्स को लेकर कांग्रेस के भीतर ही अलग-अलग राय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने सवाल उठाया था कि 2-3 ब्रिक्स सम्मेलनों से भारत को आखिर कितने ठोस फायदे मिले हैं? अब उनकी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर ने इस के महत्व और भारत को इससे होने वाले कुछ फायदों को गिनाया है। थरूर ने कहा कि ब्रिक्स ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के

शशि थरूर और पी. चिदंबरम

लिए अहम मंच है। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा देश हैं, लेकिन इसमें 11 प्रमुख देश विचारों को सामने रखते हैं।

भारत को जारी करनी पड़ी थी चेयर की घोषणा

थरूर ने कहा कि विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच साझा घोषणा पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद भारत ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर अपनी ओर से चेयर की घोषणा जारी की थी। अगर फिर साझा बयान पर सहमति नहीं बनती है तो कुछ लोग इसे झटका मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों के मतभेदों को संभालना और उनके बीच सहमति बनाना भारतीय राजनयिकों के सामने बड़ी चुनौती होगी।

खालिद के समर्थन में नारे लगाना राष्ट्र विरोधी नहीं

मुंबई की एक कोर्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के छात्र अभिरूप आशीष पॉल को जमानत दे दी है। पॉल को जेल में बंद दिल्ली दंगों के

आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दत्तात्रेय शंकरराव खेडेकर ने टिप्पणी की कि पॉल से पहले ही पर्याप्त समय तक हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है। उन्हें किसी माओवादी या अन्य प्रतिबंधित संगठन से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है। नप्रथम दृष्टया संदेह के अलावा आरोपी की गतिविधियों को माओवादी मानसिकता से जोड़ने या राष्ट्र के विरुद्ध या भारत के खिलाफ प्रतिबंधित संगठन से संबद्ध होने का कोई सबूत नहीं है।

महोबा में फसल सर्वे के नाम पर वसूली

सर्वेयरों को पहना दी चूड़ी पेटीकोट और जूतों की माला

एजेंसी ⏭ महोबा

फसल सर्वे के नाम पर किसानों से रुपए वसूले जाने के आरोप से भड़के ग्रामीणों ने 2सर्वेयरों को पकड़कर अनोखा विरोध किया। कोतवाली चरखारी क्षेत्र के नटर्रा गांव में ग्रामीणों ने दोनों सर्वेयरों को महिलाओं के कपड़े और चूड़ियां पहनाई। इसके बाद गले में जूतों की माला डालकर पूरे गांव में घुमाया। इसके बाद दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। कृषि विभाग और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले में लगातार हुई बारिश से

उड़द, मूंग, तिल और मूंगफली की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का दावा है कि कई जगह फसलें 90 फीसदी तक खराब हो गई हैं और खेतों में अब भी पानी भरा है। किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया था और नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर दी थी।

गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम

भारत में एचपीवी वैक्सीन की 80 लाख खुराकें दी जा चुकी

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

भारत ने गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के प्रयासों में अहम उपलब्धि हासिल की है। फरवरी 2026 में शुरू हुए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) वैक्सीन की 80 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। यह उपलब्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के जरिए एचपीवी टीकाकरण की बढ़ती पहुंच को दर्शाती है और किशोरियों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने

के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। टीकाकरण अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री की ओर से फरवरी 2026 में किया गया था। 14 वर्ष की लड़कियों को माता-पिता की सहमति से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वैच्छिक और निःशुल्क एकल खुराक एचपीवी टीकाकरण प्रदान किया जाता है।

बैंक फ्रॉड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गया से गुरुग्राम और दिल्ली तक 9 ठिकानों पर छापेमारी

131.79 करोड़ रुपए का घालमेल

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गया के

एक होटल ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने गया में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड, इसके निदेशक अखौरी गोपाल और उनके बेटों निशांत और नितेश से जुड़े मामले में की। यह मामला सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर दर्ज किया गया है। कथित अपराध से जुड़ी राशि करीब 131.79 करोड़ बताई गई है। ईडी का आरोप है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह ने करीब 85 करोड़ का लोन दिया था। इसमें से लगभग 58 करोड़ गलत तरीके से दूसरी जगह इस्तेमाल किया। कुछ संपत्तियां गिरवी रखी।

डीआरएम ऑफिस से 50 हजार की रिश्वत में अरेस्ट

प्रयागराज। प्रयागराज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय (डीआरएम) में

सीबीआई ने सहायक कार्मिक अधिकारी और कार्यालय अधीक्षक को कथित तौर पर 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोको पायलट के स्थानांतरण के मामले में दोनों आरोपी हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी का बड़ा ऐलान

देश में मार्च 2027 तक लागू होगा बैरियर फ्री रूल

टोल प्लाजा का नया नियम तैयार, सरकार 'वन टैग' सुविधा भी शुरू करेगी

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। भारत अब पूरी तरह से डिजिटल और बैरियर-फ्री टोलिंग प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि नई एआई आधारित प्रणाली मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है, जिसके बाद गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। इससे सालाना टोल राजस्व में करीब 10,000 करोड़ की बढ़ोतरी का अनुमान है। इसके साथ ही सरकार 'वन टैग' सुविधा भी शुरू करने जा रही है, जिससे बिना नया फास्टैग खरीदे अपना बैंक अकाउंट आसानी से बदल सकेंगे।

टोल चौकियों पर नहीं रुकना पड़ेगा

गडकरी ने घोषणा की कि इसके चालू होने के बाद वाहन चालकों को टोल चौकियों पर बिना रुके गुजरने की सुविधा मिलेगी। एआई और निर्बाध टोल प्रणाली के जरिए टोल पर रुकने की व्यवस्था हटेगी।

इस तरह काम करेगी यह

यह नई व्यवस्था टोल वसूली के लिए स्वचालित वाहन नंबर प्लेट पहचान और फास्टैग को आपस में एकीकृत (इंटीग्रेट) करेगी। इससे टोल प्लाजा पर वाहनों का वेटिंग टाइम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यदि फास्टैग का बैंक बदलना चाहते हैं, तो नया टैग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

80 से 90 प्रतिशत तक वेटिंग समय घटा

फास्टैग की सफलता का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसे 2014 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था और 2021 में अनिवार्य कर दिया गया। आज देश के 98 फीसदी से अधिक वाहनों में फास्टैग का उपयोग हो रहा है और 13 करोड़ से अधिक टैग जारी किए जा चुके हैं। फास्टैग ने पहले के 12 से 30 मिनट के प्रतीक्षा समय को 80 से 90 प्रतिशत तक घटा दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर फास्टैग का उपयोग अब 98 प्रतिशत से अधिक हो गया है। अब तक देश में 13 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस नई बाधा-मुक्त डिजिटल टोलिंग प्रणाली से जहां वाहन चालकों के समय की बचत होगी,पारदर्शिता भी आएगी।

नीति आयोग के सीईओ बोले

2047 तक विकसित देश बनने के लिए समावेशी वृद्धि जरूरी

एजेंसी ⏭ मुंबई

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनुराग जैन ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है और 2047 तक विकसित देश बनने के लिए उसे समावेशी वृद्धि की जरूरत है। जैन ने वैश्विक फिनटेक सम्मेलन में कहा कि कुछ राज्यों ने स्वास्थ्य और शिक्षा के मानकों पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन कुछ राज्य पीछे रह गए हैं, इसलिए हमें उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आर्थिक समावेश के जरिए

अनुराग जैन

समृद्धि हासिल करने के लिए भारत के पास मजबूत आधार है। इसके तहत सभी लोगों को उचित शिक्षा और लाभकारी रोजगार या उद्यमिता के लिए कौशल तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। हम विकसित राष्ट्र बनने के लिए समावेशी वृद्धि चाहते हैं। आय के स्तर पर जब प्रति व्यक्ति आय को मापते हैं, तो केवल यह पर्याप्त नहीं है।

खेल प्रतिभाओं को संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे: मुख्यमंत्री

रायपुर में 60 करोड़ की आर्चरी अकादमी, जशपुर के पंडरापाठ में भी 25 करोड़ की अकादमी बनेगी

40वें नेशनल गेम्स की मेजबानी के लिए छत्तीसगढ़ करेगा प्रयास

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। गांवों, वनांचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, बस उनकी समय पर पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधन और अवसर देने की जरूरत है। राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है और प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए संसाधनों और अवसरों की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री साय राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की एग्जीक्यूटिव बॉडी और जनरल काउंसिल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे।

प्रमुख घोषणाएं

1. शासन और ओलंपिक संघ में बेहतर समन्वयः खेल संघों की जरूरतों और प्रस्तावों के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के साथ समन्वय की विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी।

2. रायपुर में 60 करोड़ की आर्चरी अकादमीः रायपुर, रायगढ़ और कुनकुरी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। रायपुर में लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक आर्चरी अकादमी का निर्माण किया जा रहा है।

3. जशपुर के पंडरापाठ में भी अकादमीः जशपुर अंचल में तीरंदाजी की नैसर्गिक प्रतिभा को देखते हुए पंडरापाठ में 20-25 करोड़ रुपए की लागत से आर्चरी अकादमी स्थापित की जा रही है। इससे पहाड़ी कोरवा सहित वनांचल की प्रतिभाओं को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा।

4. 40वें नेशनल गेम्स की मेजबानी का प्रयासः बैठक में 40वें नेशनल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में कराने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए शासन स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। यदि मेजबानी मिलती है तो आयोजनों को बस्तर से भी जोड़ने पर विचार किया जाएगा।

बस्तर और सरगुजा ओलंपिक से मिल रहा बड़ा मंच

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर और सरगुजा ओलंपिक ने दूरस्थ क्षेत्रों के हजारों युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है। बस्तर ओलंपिक का आयोजन हर साल किया जाएगा। खेल उत्कर्ष मिशन के जरिए प्रतिभाओं को तराशने पर जोर दिया जा रहा है। खेल केवल पदक तक सीमित नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम हैं।उन्होंने खेल संघों को उद्योग समूहों से जोड़ने की पहल तेज करने को कहा, ताकि प्रशिक्षण, उपकरण और अधोसंरचना के लिए अतिरिक्त संसाधन मिल सकें। उन्होंने बताया कि खेल अलंकरण समारोह की पुनः शुरूआत और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में अवसर देने से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वनांचल में तीरंदाजी और मलखंब की अपार संभावनाएं हैं। सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों का तेजी से विस्तार हुआ है। बैठक में ओलंपिक दिवस आयोजन, जिला ओलंपिक संघों के विस्तार, हैंडबॉल एसोसिएशन सहित विभिन्न संघों के विषयों पर चर्चा हुई।इस अवसर पर महासचिव डॉ. विक्रम सिसोदिया सहित संघ के पदाधिकारी और विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर मंथन, मुंबई में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक हितों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुंबई में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। 11 और 12 सितंबर 2026 तक आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के निर्माण श्रमिकों के सुरक्षित, सम्मानजनक और समृद्ध भविष्य पर विस्तृत चर्चा की गई। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे, मध्यप्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और छत्तीसगढ़ के श्रम सचिव हिम शिखर गुप्ता सहित विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह तथा मंडल सचिव गिरीश रामटेके ने किया। सम्मेलन के दौरान विभिन्न राज्यों ने श्रमिक हित में लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों और नए नवाचारों के अनुभवों को साझा किया। साथ ही निर्माण श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भविष्य की रणनीतियों पर रणनीति तैयार की जा रही है।

यह आयोजन देश के निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने आईसीएआर-एनआईबीएसएम के कार्यों की सराहना की

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद विमानतल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम तथा वरिष्ठ अधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर के निदेशक डॉ. पी. के. राय ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की तथा संस्थान द्वारा संचालित अनुसंधान कार्यक्रमों, तकनीकी हस्तक्षेपों एवं प्रमुख पहलों की जानकारी दी। उन्होंने राज्य के कृषि विभाग के साथ समन्वय से भारतीय कृषि को सुदृढ़ बनाने के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया। डॉ. राय ने फसलों में कीट-व्याधियों, रोगों एवं अन्य जैविक तनावों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में आईसीएआर-एनआईबीएसएम द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने फसल उत्पादकता, कृषि की प्रतिरोधक क्षमता तथा किसानों की आय में वृद्धि के लिए विकसित की जा रही सतत एवं किसानोन्मुख तकनीकों पर भी प्रकाश डाला। श्री चौहान ने संस्थान के कृषि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास में योगदान की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में स्थापित आईसीएआर-एनआईबीएसएम एक प्रमुख प्रा{ संस्थान के रूप में विशेष महत्व रखता है। उन्होंने संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों, नवाचारों एवं किसान-केंद्रित पहलों का अवलोकन करने के लिए निकट भविष्य में आईसीएआर-एनआईबीएसएम का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने उभरती कृषि चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में आईसीएआर-एनआईबीएसएम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की। यह मुलाकात केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि अनुसंधान को सुदृढ़ करने, फसल तनावों के प्रभावी प्रबंधन तथा किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने के साझा संकल्प को प्रतिबिंबित करती है।

ओवररेटिंग की शिकायतों पर आबकारी विभाग का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर, 11 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश की कई प्रीमियम शराब दुकानों में एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचने की शिकायतों के बाद आबकारी विभाग ने सख्त कदम उठाया है।विभाग ने प्रदेश की सभी प्रीमियम शराब दुकानों को कैशलेस करने का फैसला लिया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है।जारी आदेश के अनुसार, अब प्रदेश की किसी भी प्रीमियम शॉप पर ग्राहक कैश में भुगतान नहीं कर पाएंगे। शराब खरीदने के बाद पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा।

डिलीवरी बॉय पर 10-15 मिनट में सामान पहुंचाने का दबाव नहीं, कंपनियों को पुलिस की सख्त हिदायत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर । राजधानी में ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की सड़क सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस उपायुक्त यातायात एवं प्रोटोकॉल डॉ. अर्चना झा ने विभिन्न ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों और फर्मों के संचालकों व मैनेजरों की बैठक ली। बैठक में डिलीवरी बॉय के लिए यातायात नियमों का पालन, पुलिस चरित्र सत्यापन और तय समय सीमा में सामान पहुंचाने के दबाव को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, डिलीवरी डॉट कॉम, ब्लिंकिट सहित अन्य डिलीवरी कंपनियों के मैनेजर और प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात राम कुमार बर्मन, सहायक पुलिस आयुक्त सतीश ठाकुर और रमेश येरेवार भी उपस्थित रहे।

पुलिस ने दिए ये सख्त निर्देश

1. समय सीमा का दबाव न बनाएंः यातायात पुलिस ने कंपनियों को समझाइश दी कि डिलीवरी बॉय पर 10 या 15 मिनट जैसी तय समय सीमा में सामान पहुंचाने का अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाए। समय की पाबंदी के कारण कर्मचारी हड़बड़ी में तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।

2. यातायात नियमों का पालन अनिवार्यः सभी डिलीवरी एजेंटों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य, रॉन्ग साइड वाहन नहीं चलाना, ओवरस्पीडिंग से बचना और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।

3. चरित्र सत्यापन जरूरीः चूंकि ऑनलाइन डिलीवरी कर्मचारी सीधे लोगों के घरों और प्रतिष्ठानों तक पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक डिलीवरी कर्मी का पुलिस चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री निवास में तीजा-पोरा तिहार की धूम, दिखी छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास में शनिवार को तीजा-पोरा तिहार के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। सुबह से ही मुख्यमंत्री निवास में तीजा की पूजा और शुभ कार्यक्रम की शुरूआत हो गई थी। इस दौरान पूरे परिसर में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपरा और संस्कृति की मनमोहक झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आतिथ्य में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में तीजा पर्व की पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। तीजा जहां महिलाओं के लिए मायके, परिवार और रिश्तों की भावनाओं से जुड़ा पर्व है, वहीं पोरा तिहार खेती-किसानी और पशुधन के प्रति आस्था और सम्मान का प्रतीक है। इस दिन मिट्टी से बने नंदी-बैल और पारंपरिक खिलौनों की पूजा करने की परंपरा है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजन के दौरान लोकगीतों की गूंज, पारंपरिक नृत्य, झूले और छत्तीसगढ़ी पकवानों ने उत्सव की रौनक को और बढ़ा दिया।

उच्च शिक्षा मंत्री की पहल पर कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि 19 सितंबर तक बढ़ी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा की पहल पर छात्रहित को देखते हुए कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त सीटों पर छात्र 19 सितंबर 2026 तक प्रवेश ले सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार, सत्र 2026-27 के लिए पूर्व में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई थी। हालांकि, कई छात्र-छात्राओं के आवेदन और सीटें रिक्त होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तिथि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इस मामले पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं और छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी मेधावी या इच्छुक छात्र का साल खराब न हो, इसी सोच के साथ प्रवेश की तिथि बढ़ाई गई है। इस निर्णय से उन सभी विद्यार्थियों को अवसर मिलेगा जो किसी कारणवश अब तक दाखिला नहीं ले पाए थे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जो छात्र-छात्राएं अभी तक प्रवेश नहीं ले पाए हैं, वे जल्द प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करें। जारी निर्देश के तहत, उच्च शिक्षा संचालनालय को निर्देशित किया गया है कि वे सभी संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त सीटों की स्थिति के आधार पर 19 सितंबर तक पारदर्शी प्रक्रिया से प्रवेश संपन्न कराएं। शासन के इस फैसले से प्रदेशभर के हजारों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने राहत की सांस ली है।

डिजिटल एडिक्शन आज किसी भी अन्य एडिक्शन से अधिक खतरनाक: राज्यपाल रमेन डेका

आईसीएफएआई विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका आज आईसीएफएआई विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में शैक्षणिक सत्र 2025 एवं 2026 के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कुल 504 विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की गईं, जिनमें 19 को गोल्ड मेडल और 16 को सिल्वर मेडल से नवाजा गया।

तकनीक का सदुपयोग करें, दुष्प्रभावों से बचें - राज्यपाल

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल डेका ने कहा कि आप इंटरनेट युग के विद्यार्थी हैं, जबकि हम चाक, पेंसिल, पुस्तकों और गुरुओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले दौर के विद्यार्थी हैं।उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत जरूरी है, लेकिन इसका उपयोग उतना ही होना चाहिए, जितना मानव समाज के हित में आवश्यक है। आज डिजिटल एडिक्शन किसी भी अन्य एडिक्शन से अधिक खतरनाक हो गया है। विद्यार्थियों को तकनीक का सदुपयोग करते हुए इसके दुष्प्रभावों से बचना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और माइक्रो प्लास्टिक आज दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। 21वीं सदी में विकास के साथ उसके दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा और सतत विकास को प्राथमिकता देनी होगी।

कर्मयोग का दिया संदेश

राज्यपाल ने भगवत गीता के कर्मयोग का संदेश देते हुए कहा कि कर्म ही जीवन है। हमें इस बात की चिंता किए बिना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अपने कर्म, पढ़ाई और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपका ज्ञान कोई आपसे नहीं छीन सकता। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और सही रास्ते पर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने ज्ञान और डिग्री इसलिए हासिल की है कि उसका उपयोग मानव समाज के हित में हो। विज्ञान, तकनीक और इनोवेशन का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में है और यह देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। अब छत्तीसगढ़ को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में भी प्रयास करने की आवश्यकता है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज के प्रत्येक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को अपने जीवन का रोडमैप तैयार कर योजनाबद्ध ढंग से सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने तथा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य एवं डिफेंस साइंटिस्ट डॉ. वी. सतीश रेड्डी तथा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर आर.पी. कौशिक ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। स्वागत भाषण कुलपति प्रोफेसर डॉ. शिव दयाल पांडे ने दिया।

पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाएं योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ : पाटले

0 जिपं सीईओ ने समीक्षा बैठक में दिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश
0 जिलेभर में सेवा संकल्प के तहत लगेंगे हेल्थ कैंप

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिला पंचायत सीईओ एवं ओआईसी हेल्थ विजेंद्र सिंह पाटले की अध्यक्षता में यहां संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में सर्वप्रथम आधार आधारित उपस्थिति की समीक्षा की गई। जिला पंचायत सीईओ ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शत-प्रतिशत आधार अटेंडेंस दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि आधार अटेंडेंस दर्ज नहीं करने वाले कर्मचारियों के आगामी माह के वेतन के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। जिपं सीईओ श्री पाटले ने सेवा संकल्प अभियान के तहत आगामी दिनों में जिले के प्रत्येक विकासखंड में हेल्थ कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। इन शिविरों में स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार के साथ आयुष्मान कार्ड एवं वय वंदन कार्ड बनाए एवं वितरित किए जाएंगे। उन्होंने पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड एवं आधार लिंकिंग का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक शत-प्रतिशत पहुंचाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने संस्थागत प्रसव की समीक्षा करते हुए कम संस्थागत प्रसव वाले स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभारियों को संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान मातृ मृत्यु के प्रकरणों की डेथ ऑडिट रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई। 60 वर्ष से अधिक आयु की मितानिनों के कार्य एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करने तथा कार्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में पर्याप्त मात्रा में आरडी किट उपलब्ध रखने तथा संदिग्ध मरीजों को स्वास्थ्य संस्थाओं में बुलाकर मलेरिया की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए ।

उन्होंने गर्भवती महिलाओं का गर्भावस्था के प्रथम तीन माह के भीतर शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली गर्भवती महिलाओं का अनिवार्य रूप से पंजीयन कर उन्हें समय पर आवश्यक जांच, उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होने सभी गर्भवती महिलाओं की आवश्यक जांच एवं फोर्थ एएनसी पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया। शिशु मृत्यु एवं नवजात शिशुओं की देखभाल से संबंधित सेवाओं की समीक्षा करते हुए जोखिम वाले नवजात एवं शिशुओं की समय पर पहचान, उपचार एवं आवश्यकतानुसार रेफरल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री पाटले ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मरीजों को केवल चिकित्सकीय आवश्यकता एवं स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर ही उच्च स्वास्थ्य संस्था में रेफर करें।

बैठक में एनसीडी कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। सभी विकासखंडों को निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने तथा गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, पंजीयन, उपचार एवं फॉलोअप की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ ने मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियों की जानकारी ली गई तथा शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एचएमआइएस पोर्टल में गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध डाटा एंट्री सुनिश्चित करने तथा आरसीएच 2.0 में शत-प्रतिशत ऑनबोर्डिंग एवं आवश्यक प्रविष्टियां पूर्ण करने की स्थिति की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लंबित प्रविष्टियों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान टेलीमेडिसिन सेवाओं की उपलब्धि एवं उपयोगिता, पीएम जेएवाइ एवं एसव्हीएनएएसवाइ के अंतर्गत प्रगति एवं उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई।

जिला पंचायत सीईओ श्री विजेंद्र सिंह पाटले ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को शासन की स्वास्थ्य योजनाओं एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति, पोर्टल पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण डाटा एंट्री, लंबित कार्यों के शीघ्र निराकरण तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रमों की प्रगति में सुधार एवं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समन्वित प्रयास और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.डी. पैकरा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक संदीप नामदेव सहित जिले के समस्त विकासखंडों के बीएमओ, बीपीएम, बीडीएम, बीटीईओ, जिला स्तर पर संचालित समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, कार्यक्रम कंसल्टेंट एवं डीडीएम उपस्थित रहे।

फील्ड विजिट बढ़ाएं अधिकारी, मौके पर देखें राजस्व कार्यों की प्रगति : दुग्गा

राजस्व की बैठक में संभागायुक्त ने पांच साल पुराने मामलों को निपटाने के दिए निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने कहा कि राजस्व विभाग का काम सीधे आम लोगों से जुड़ा है। इसलिए राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने तथा तीन वर्ष से अधिक पुराने मामलों को चिन्हांकित कर तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए।

संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में संभागायुक्त ने अनुविभागवार एवं तहसीलवार लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन और फौती नामांतरण जैसे प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में निपटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाहर न हो। संभागायुक्त ने कहा कि जिन सामान्य राजस्व मामलों का निराकरण स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है, उनके लिए ग्राम पंचायतों में सूचना प्रसारित कर विशेष शिविर आयोजित करें। इससे ग्रामीणों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए बार-बार तहसील और जिला कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अधिकारियों को आम जनता से सीधे संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर समाधान की दिशा में कार्य करने को कहा। बैठक में नक्शा बंटांकन, अभिलेखों की शुद्धता और लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। श्री दुग्गा ने

अधिकारियों को नियमित रूप से राजस्व न्यायालय संचालित करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदारों को रिकॉर्ड रूम में पुराने दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण के बाद संबंधित अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड रूम में भेजने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा।

संभागायुक्त ने कहा कि अधिकारियों का काम केवल कार्यालय तक सीमित नहीं होना चाहिए। अधिकारी मैदानी क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर अधीनस्थ अमले के कामकाज की निगरानी करें। संभाग में एग्रीस्टैक पंजीयन की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को फॉलोअप कर शत-प्रतिशत पंजीयन पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से नियमित निगरानी करते हुए पंजीयन की प्रगति में तेजी लाने को कहा। इस दौरान उन्होंने फसल सर्वे की भी जानकारी ली तथा मैदानी स्तर फील्ड विजिट कर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्व प्रकरणो के निराकरण में कम प्रगति वाले क्षेत्रों पर नाराजगी व्यक्त करते संबंधितो तहसीलदार को सो कास नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों से कहा कि आगामी समीक्षा बैठक में प्रगति की पुन: समीक्षा की जाएगी सभी अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन करते प्रगति लाये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगली समीक्षा में दिए गए निर्देशों का असर कार्यों की प्रगति में दिखाई देना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में राजस्व विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने अधिकारियों को शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ताकि प्रकरण अनावश्यक रूप से उच्च स्तर पर एस्केलेट न हों। उन्होंने अधिकारियों को लंबित शिकायतों की नियमित जांच कर निराकरण करने को कहा।कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त आर.के. खूंटे, श्रीमती शारदा अग्रवाल, अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा सहित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

महाविद्यालय में मना राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा के महत्व, उपयोग और रोजगार की संभावनाओं पर रखे विचार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां के रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय में राष्ट्रीय हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिंदी भाषा के महत्व, विकास, वर्तमान स्थिति तथा हिंदी के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों द्वारा विचार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में हिंदी भाषा को भारतीय संस्कृति, एकता एवं राष्ट्रीय पहचान से जोड़ते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया तथा स्वरचित कविताओं का वाचन किया गया।

एम.ए. हिंदी के छात्र सूरज ने कहा कि हिंदी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए दैनिक जीवन में हिंदी भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। अन्य छात्राओं ने भी हिंदी भाषा के विकास एवं उन्नति के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किया। सहायक शिक्षिका सुश्री रोशनी यादव ने हिंदी भाषा के प्रति सम्मान की भावना को निरंतर बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सहायक प्राध्यापक बुद्धलाल साहू ने हिंदी भाषा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने हिंदी भाषा का विकास, राजनीतिक स्थिति एवं हिंदी, वर्तमान परिदृश्य में हिंदी की स्थिति तथा हिंदी भाषा से जुड़े रोजगार के अवसरों पर विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों को हिंदी के अध्ययन के साथ इसके व्यावहारिक एवं रोजगारपरक पक्ष को समझने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक बुद्धलाल साहू, सहायक शिक्षिका सुश्री रोशनी यादव तथा एम.ए. हिंदी प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कार्यालय कलेक्टर जिला सरगुजा एवं पदेन एवं सचिव छ.ग. शासन,
अधिसूचना

अम्बिकापुर, दिनांक 07.09.2026

रा.प्र.क./202608021900001/अ-82/2025-26 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन :-

1. जिला- सरगुजा 2. तहसील- उदयपुर 3. ग्राम/प.ह.नं. - रजबांध 4. भूमि का क्षेत्रफल - 2.024 हेक्टेयर

खसरा न.	रकबा (हे.मे)	खसरा न.	रकबा (हे.मे)
295/1	0.405	219/5	0.113
294	0.012	219/4	0.032
224/2	0.085	218/2	0.081
225	0.008	218/1	0.153
223/2	0.052	230/1	0.032
227/1	0.028	230/3	0.028
227/2	0.045	234	0.109
227/3	0.065	235	0.089
228	0.263	233/4	0.081
218/3	0.028	276/1	0.085
219/2	0.214	220/3	0.016

कुल खसरा 22 कुल रकवा 2.024 हे0

धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0-1. अम्बिकापुर

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण - रजबांध (डूमरडीह) जलाशय योजना के निर्माण हेतु ग्राम रजबांध के मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु।

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता लोक प्रयोजन के औचित्य तथा समाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिये कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिये अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर जिला सरगुजा को पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(राम राज सिंह)
भू-अर्जन अधिकारी
उदयपुर

(अजीत बसंत)
कलेक्टर, सरगुजा
एवं पदेन उप सचिव छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जी-262703248/1

आम सूचना

मैं श्रीमती गीता लिण्डा, पति स्व. श्री गोपाल लिण्डा, उम्र- 65 वर्ष, निवासी ग्राम भगवानपुर कला, थाना- गाँधीनगर अम्बिकापुर जिला- सरगुजा छ.ग. निवासी हूँ। ग्राम भगवानपुर - कला मे मेरे स्वामित्व की भूमि जिसका पुराना खसरा नं. 176/5, रकबा 0.040 हे. वर्तमान री नम्बरिंग खसरा नं. 282, रकबा 0.040 भूमि को दिनाँक 30/5/1983 को क्रय की हूँ। मैं उक्त भूमि पर लोन लेकर मकान का निर्माण कर रही हूँ। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनाँक 28/09/2026 के पूर्ण आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

श्रीमती गीता लिण्डा
ग्राम- भगवानपुर कला
अम्बिकापुर- सरगुजा (छ.ग.)
मो. 97552-30840

शासकीय भूमि के अधिकार अभिलेख में कूटरचना कर करा दी जमीन की रजिस्ट्री

0 वृद्धा को झांसा देकर कराया हस्ताक्षर, 8 माह बाद जमीन बेचने का मामला आया सामने 0 जिला प्रशासन से शिकायत, कार्रवाई की मांग

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सरकारी भू-अभिलेख में कथित कूटरचना कर जमीन के बिक्री विलेख पंजीकृत कराने का मामला सामने आया है। मामले में जांच व कार्रवाई हेतु प्रेमनगर क्षेत्र के ग्राम रघुनाथपुर की रनमेत ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है। शिकायत में एक व्यक्ति पर मकान निर्माण के लिए शासकीय सहायता दिलाने का झांसा देकर दस्तावेज तैयार कराने और बाद में जमीन को अन्य लोगों को बेच देने का आरोप लगाया गया है। अधिकारीद्वय को दिए शिकायत पत्र में प्रकाश कुमार, प्रेमदास मानिकपुरी, प्रभा साहू, धनजीत साहू, विनोद कुमार साहू तथा एम.आर. यादव, उप-पंजीयक सूरजपुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बृद्धा रनमेत का कहना है कि उसके भाइयों ने मायके में उसे करीब 5 डिसमिल भूमि मकान बनाने के लिए दी थी। उसके पास मकान निर्माण के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। इसी बात की जानकारी गांव के प्रकाश पनिका को होने पर वह जनवरी 2026 में उसके पास आया और शासन से मकान बनाने के लिए पैसा दिलाने का भरोसा दिया।

और सूरजपुर जाकर कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को आवेदन देने के लिए लिखा-पढ़ी कराने की बात कही। इसी दौरान शिकायतकर्ता के छोटे भाई सहदेव को भी मामले की जानकारी हुई। शिकायत में आगे बताया गया है कि सहदेव ने अपने निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास के बगल में अपने बेटों के लिए अतिरिक्त कमरा बनाने की योजना बताई थी। पुलिस अधीक्षक को 10 सितंबर को दी गई रिपोर्ट में बताया कि पूर्व में दी गई शिकायत के बाद जब

उसने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में लगाए गए दस्तावेजों और किसी गहबर नामक व्यक्ति के पुराने अधिकार अभिलेख की प्रमाणित प्रति को देखा, तब उसे कथित गड़बड़ी का पता चला। आरोप है कि प्रकाश कुमार ने उससे और उसके छोटे भाई सहदेव से छल-कपट करके करीब आठ महीने पहले अलग-अलग मुख्तारनामा तैयार करवाए। इसके बाद कथित तौर पर उनकी जमीन को अन्य लोगों के पक्ष में बेच दिया गया और बिक्री की पूरी रकम प्रकाश कुमार द्वारा प्राप्त कर ली गई।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि गांव में मामले की सच्चाई सामने न आए, इसके लिए प्रकाश कुमार ने अपने भांजे प्रेमदास मानिकपुरी को भी कथित रूप से इस प्रक्रिया में शामिल किया। शिकायतकर्ता के मुताबिक प्रेमदास तथा जमीन के कथित खरीदार प्रभा साहू, धनजीत साहू और विनोद कुमार साहू को मुख्तारनामा और दोनों बिक्री विलेखों में गवाह बनाया गया। मामले का सबसे गंभीर पक्ष अधिकार अभिलेख में कथित कूटरचना से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बिक्री विलेख के पंजीयन के लिए जमीन का उल्लेख सरगुजा स्टेट सेटलमेंट में होना जरूरी था। इसी उद्देश्य से कथित तौर पर तहसील न्यायालय प्रेमनगर से गहबर नामक व्यक्ति के पुराने अधिकार अभिलेख की प्रमाणित नकल प्राप्त की गई। शिकायत में दावा किया गया है कि उस दस्तावेज में दर्ज खसरा नंबर 42 को कथित रूप से बदलकर 43 किया गया। इसी तरह खसरा नंबर 45/2 को कथित रूप से 45/5 कर दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन्हीं कथित रूप से बदले हुए विवरण के आधार पर फर्जी एवं कूटरचित बिक्री विलेख तैयार कर उसकी और उसके छोटे भाई सहदेव की सड़क किनारे स्थित जमीन को बेचने की कार्रवाई की गई। शिकायत में उप-पंजीयक एम.आर. यादव की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि अधिकार अभिलेख के वास्तविक खसरा नंबर 42 और 45/2 में कथित कूटरचना किए जाने के बावजूद संबंधित दस्तावेजों की जांच में इसे नजरअंदाज कर बिक्री विलेखों का पंजीयन कर दिया गया। रनमेत ने अपनी शिकायत में कहा है कि बाद में उसने गहबर नामक व्यक्ति के पुराने अधिकार अभिलेख की असल प्रमाणित नकल प्राप्त की और उसे दोनों बिक्री विलेखों के साथ संलग्न अधिकार अभिलेख की नकल से मिलान कराया। इसी मिलान के दौरान उसे सरकारी दस्तावेज में कथित कूटरचना की जानकारी हुई। पुलिस को दिए आवेदन के साथ दोनों मुख्तारनामा, दोनों बिक्री विलेख तथा गहबर नामक व्यक्ति के पुराने अधिकार अभिलेख की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने की बात भी कही है। मामले को लेकर पहले कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद 10 सितंबर को प्रकाश कुमार, प्रभा साहू, धनजीत साहू और विनोद कुमार साहू के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित शिकायत की गई है। उल्लेख है। महिला ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज जांच कराने हेतु मांग की है।

गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष के भतीजे के साथ बेरहमी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया

पुलिस के हाथ अभी तक लगा है एक टुटपुंजिया आरोपी

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के समलाया मंदिर के पास तीन दिन पूर्व गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के भतीजे पर हुए जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज वायरल होने के बाद शहर में दहशत का माहौल है और कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपियों ने इस दौरान 2500 रूपये लूट की घटना को भी अंजाम दिया था।

मारपीट का यह है पूरा मामला

पीड़ित अभिरत सिंहदेव पिता अमिताभ सिंहदेव, निवासी पंजाब गार्डन के पीछे, मनेन्द्रगढ़ रोड का रहने वाला है। अभिरत घटना दिनांक 7 सितम्बर की शाम करीब 6 बजे की है। वह अपने दोस्त देव दुबे के साथ स्कूटी से महामाया पारा निवासी शकील फिरदौसी के पास रायफल शूटिंग के संबंध में बात करने जा रहा था। इसी दौरान समलाया मंदिर के पास गोलू पठान और राज बंगाला ने उसकी स्कूटी रोक ली। दोनों ने अभिरत से रुपये मांगे। जब उसने पैसे देने से मना किया तो आरोपियों ने जबरन उसकी जेब से 2500 रुपये निकाल लिए।

पैसे लूटने के बाद 12 लड़कों ने घेरा

रुपये छीनने के बाद गोलू पठान अपने अन्य साथियों को बुला लिया। देखते ही देखते मौके पर 10 से 12 लड़कों का झुंड इकट्ठा हो गया। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे दुकान के बाहर रखे गैस सिलेंडरों के पास दो स्कूटी खड़ी हैं और भीड़ ने अभिरत को बीच सड़क पर घेर रखा है।शुरुआत में धक्का-मुक्की और गाली-गलौज होती है, फिर सभी मिलकर अभिरत पर टूट पड़ते हैं, और बेरहमी से पीटा जाता है। इसी दौरान एक सफेद एसयूवी भी मौके पर आती है।

आरोपियों को कौन दे रहा अभयदान

घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन चार दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी अब तक फरार हैं। ऐसे में शहर में चर्चा आरोपियों को अभयदान देने की भी हो रही है। घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई बेहद धीमी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समलाया मंदिर क्षेत्र में शाम ढलने के बाद असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है, लेकिन पुलिस गश्त नहीं करती। इस घटना के बाद व्यापारियों और आम लोगों में आक्रोश है।

नेशनल लोक अदालत में 5200 से अधिक प्रकरणों का निपटारा

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश पर शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर सहित जिले के न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में आयोजित लोक अदालत में न्यायालयों के 3000 से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं राजस्व न्यायालयों में भी 2200 से अधिक प्रकरणों का निराकरण हुआ। किशोर न्याय बोर्ड के चार और परिवार न्यायालय के 13 प्रकरणों का आपसी राजीनामे के आधार पर निराकरण किया गया। लोक अदालत में लंबे समय से लंबित कई प्रकरणों का आपसी सहमति से समाधान हुआ। द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमित कुमार सोनी की खंडपीठ में मोटर दुर्घटना से जुड़े एक मामले में मृतक के परिजनों को 22.50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दिलाई गई।

22.50 लाख क्षतिपूर्ति दिलाकर प्रकरण का निराकरण

मामला 9 जून 2024 का है। ग्राम बरियो बस स्टैंड के पास दोपहर करीब 3 बजे हाईवा ट्रक से सड़क का पत्थर उछलकर सूरज केशरी के माथे के बाईं ओर कनपटी के पास लगा था। गंभीर चोट लगने पर उसे अंबिकापुर अस्पताल ले जाया गया। यहां से रायपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद मृतक की पत्नी, बच्चों और माता-पिता ने मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के तहत क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया था। मामले में बीमा कंपनी और पक्षकारों के बीच समझौता होने पर मृतक के परिजनों को 22 लाख 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति दिलाकर प्रकरण का निराकरण किया गया।

पुराने चेक बाउंस केस में राजीनामा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की खंडपीठ में चेक बाउंस से संबंधित प्रकरण का भी राजीनामा से निराकरण हुआ। परिवादी स्व. दिलीप सिंह की ओर से उनकी पत्नी ने न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया था। इसमें 3 लाख 49 हजार रुपये की राशि को लेकर परिवादी और अभियुक्त के बीच स्वेच्छा से समझौता हुआ। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से प्रकरण समाप्त किया गया।

पांच साल पुराना विवाद भी सुलझा

सीतापुर न्यायालय में व्यवहार न्यायाधीश पूजा मंडावी की खंडपीठ में वर्ष 2021 से लंबित प्रकरण का भी निराकरण हुआ। पक्षकारों ने पुराने विवाद को भुलाकर आपसी सहमति से समझौता किया। इससे करीब पांच वर्ष से लंबित मामले का निराकरण होने के साथ दोनों पक्षों के बीच चला आ रहा विवाद भी समाप्त हो गया।

बच्चों के बीच विवाद से शुरू हुए झगड़े का समाधान

व्यवहार न्यायाधीश उत्सव तिवारी की खंडपीठ में एक ही गांव के दो परिवारों के बीच बच्चों के विवाद से शुरू हुए झगड़े का भी समाधान हुआ। बच्चों के बीच विवाद के बाद दोनों परिवारों के सदस्यों के बीच गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने की घटना हुई थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था। करीब पांच वर्ष से लंबित दोनों मामलों में पक्षकारों ने नेशनल लोक अदालत में आपसी मतभेद समाप्त करते हुए स्वेच्छा से समझौता किया। इसके बाद दोनों प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया।

श्रमिक कार्ड है मजदूर का असली सहारा, पंजीयन जीवित रखना जरूरी

सरगुजा के ग्राम सपना में युवा आयोग अध्यक्ष ने ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। विकासखंड अंबिकापुर के ग्राम पंचायत सपना के पंचायत भवन में शुक्रवार को श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष मजदूर पंजीयन कराने और पुराने कार्ड का नवीनीकरण कराने पहुंचे।

इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष पायल सिंह तोमर व राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक श्रमिक के लिए सबसे जरूरी है उसका पंजीयन और पंजीयन का जीवित रहना। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि श्रमिक कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि मजदूर परिवार के लिए सुरक्षा कवच है। इसी कार्ड के जरिए शासन की कई जनहितकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। श्रमिक पंजीयन से मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कई बार ग्रामीण पंजीयन तो करा लेते हैं, पर समय पर नवीनीकरण नहीं कराते, जिससे पंजीयन मृत हो जाता है और योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। शिविर के पायल ब विश्वविजय ने ने एक-एक ग्रामीण से उनकी बातों को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र श्रमिक पंजीयन से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, इसके लिए पंचायत स्तर पर ही ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान पंचायत भवन में सरपंच, पंच, सचिव सहित अन्य मौजूद रहे। शिविर में महिलाओं की भागीदारी अधिक देखी गई। अंत में युवा आयोग अध्यक्ष ने सभी से अपील की, वे अपना पंजीयन जीवित रखें और दूसरों को भी इसके फायदे के बारे में बताएं, ताकि कोई भी मजदूर परिवार शासन की योजनाओं से वंचित न रहे।

चार बाइकों में घूमने निकले थे 9 दोस्त, ट्रक की टक्कर से 1 की मौत, दोस्त घायल

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। गांधीनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 16 साल के स्कूली छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त घायल हो गया। मृतक की पहचान किशन यादव पिता भरत यादव 16 साल, निवासी जशपुर के रूप में हुई है। हादसा कल्याणपुर चौक और दिल्ली पब्लिक स्कूल के बीच हुआ।

प्रत्यक्षदर्शी और दोस्त सागर मण्डल पिता रवि मण्डल 17 साल निवासी सुभाषनगर नया पानी टंकी रोड ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह दशमेश पब्लिक स्कूल अंबिकापुर में कक्षा 12वीं का छात्र है। 11 सितंबर को उसकी तबीयत खराब होने के कारण वह स्कूल नहीं गया था। सुबह करीब 11 बजे उसके मोबाइल पर दोस्त अंश, रितेश और किशन का लगातार फोन आ रहा था। जब उसने किशन को कॉल बैक किया तो किशन ने उसे दशमेश कॉलेज के पास आने को कहा और घूमने चलने का प्लान बताया। सागर अपने मोटरसाइकिल से दशमेश स्कूल के पास पहुंचा तो वहां आर्यन, रितेश, रामू, अंश, किशन और अन्य दोस्त मिले। सभी 9 दोस्तों ने 4 मोटरसाइकिलों में केरता माइनिंग घूमने जाने का प्लान बनाया। एक बाइक पर किशन यादव और अंश थे, बाइक किशन चला रहा था। केरता माइंस घूमने के बाद सभी वापस घर लौट रहे थे। वापसी के दौरान सबसे आगे एक बाइक पर अंजलुस लकड़ा, तन्मय, अनिश थे, दूसरी बाइक पर रितेश और रामू, तीसरे नंबर पर किशन यादव और अंश की बाइक थी, और सबसे पीछे सागर और आर्यन थे। सागर ने बताया कि जब वह कल्याणपुर चौक और डीपीएस के बीच पहुंचा तो देखा कि किशन और अंश बीच सड़क पर गिरे पड़े हैं। मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त होकर धुआं निकल रहा था। किशन को गंभीर चोट आई थी, खून बह रहा था और वह बेहोश पड़ा था, जबकि अंश को भी चोट लगी थी लेकिन वह होश में था। घटना स्थल पर खड़े लोगों ने बताया कि किसी ट्रक चालक ने टक्कर मार दी और भाग गया। इसके बाद सागर और आर्यन ने राह चलती एक कार को रोका और उसी कार से दोनों घायलों को होलीक्रॉस अस्पताल अंबिकापुर लेकर आए। सूचना पर सभी दोस्त होलीक्रॉस अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने जांच के बाद किशन यादव को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि किशन की मौत सड़क दुर्घटना में आई गंभीर चोटों के कारण हुई है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है।

अंबिकापुर में स्वाइन फ्लू के 04 मरीज मिले, 02 रायपुर में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर और आसपास के इलाके से कुल चार मरीजों में स्वाइन फ्लू (एच 1एन 1) की पुष्टि हुई है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. शैलेंद्र गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विशेष तैयारी कर दी गई है।

डॉ. गुप्ता ने बताया कि जो चार मरीज मिले हैं, वे सभी अलग-अलग इलाके के हैं। पहला मरीज शहर के कोर्ट के पीछे का रहने वाला है, दूसरा जेल परिसर के समीप का है, तीसरा बतौली ब्लॉक का और चौथा चटिरमा इलाके का है। राहत की बात ये है कि इन चारों में से दो मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। बाकी बचे दो मरीजों का इलाज अभी रायपुर में चल रहा है। एक मरीज को एनएच एमएमआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरे का इलाज मेकाहारा (डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल) में चल रहा है। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

बाहर से आया वायरस, लोकल ट्रांसमिशन नहीं

अहम सवाल ये है कि स्वाइन फ्लू अंबिकापुर कैसे पहुंचा? इस पर डॉ. शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि अभी तक लोकल ट्रांसमिशन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। चारों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है। दो मरीज कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से लौटे थे, जबकि दो मरीज दिल्ली की यात्रा पर गए थे। आशंका है कि संक्रमण वहीं से आया है। इसलिए घबराने की नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है।

मेडिकल कॉलेज में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार

स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में 10 बेड का विशेष आइसोलेशन वार्ड बना दिया है। अगर कोई भी संदिग्ध मरीज सर्दी-खांसी, तेज बुखार, गले में दर्द और सांस लेने में तकलीफ के साथ आता है, तो उसे तुरंत वहीं भर्ती कर जांच और इलाज किया जाएगा। सभी डॉक्टरों और स्टाफ को जरूरी गाइडलाइन भी दे दी गई है और दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों को भी अलर्ट कर दिया है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए सावधान रहना जरूरी है।

डरने की नहीं ध्यान देने की जरूरत

डॉक्टर की सलाह है कि अगर 2-3 दिन से ज्यादा तेज बुखार, खांसी, बदन दर्द और सांस फूल रही है, तो खुद से दवाई नहीं खाएं, सीधे अस्पताल में जांच कराएं। भीड़ वाली जगह, बस स्टैंड, बाजार में मास्क जरूर लगाएं। हाथों को बार-बार साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, उन्हें ठंड से बचाएं। खांसते या छींकते समय मुंह पर रूमाल रखें।

श्रमिक कार्ड है मजदूर का असली सहारा, पंजीयन जीवित रखना जरूरी

सरगुजा के ग्राम सपना में युवा आयोग अध्यक्ष पायल-विश्व विजय ने ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। विकासखंड अंबिकापुर के ग्राम पंचायत सपना के पंचायत भवन में शुक्रवार को श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष मजदूर पंजीयन कराने और पुराने कार्ड का नवीनीकरण कराने पहुंचे।

इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष पायल सिंह तोमर व राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक श्रमिक के लिए सबसे जरूरी है उसका पंजीयन और पंजीयन का जीवित रहना। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि श्रमिक कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि मजदूर परिवार के लिए सुरक्षा कवच है। इसी कार्ड के जरिए शासन की कई जनहितकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। श्रमिक पंजीयन से मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी। प्रसूति सहायता, मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता सहित कई योजनाओं से संबंधित मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कई बार ग्रामीण पंजीयन तो करा लेते हैं, पर समय पर नवीनीकरण नहीं कराते, जिससे पंजीयन मृत हो जाता है और योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। शिविर के पायल ब विश्वविजय ने ने एक-एक ग्रामीण से उनकी बातों को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र श्रमिक पंजीयन से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, इसके लिए पंचायत स्तर पर ही ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान पंचायत भवन में सरपंच, पंच, सचिव सहित अन्य मौजूद रहे। शिविर में महिलाओं की भागीदारी अधिक देखी गई। अंत में युवा आयोग अध्यक्ष ने सभी से अपील की, वे अपना पंजीयन जीवित रखें और दूसरों को भी इसके फायदे के बारे में बताएं, ताकि कोई भी मजदूर परिवार शासन की योजनाओं से वंचित न रहे

आबकारी उड़नदस्ता ने 21 लीटर महुआ शराब के साथ स्कूटी सवार को पकड़ा

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम ने 21 लीटर महुआ शराब परिवहन करते हुए आदतन आरोपी राजेंद्र सिंह सरदार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी की यामहा स्कूटी सीजी 15 ईएल 3101 भी जब्त की गई है।

मध्यप्रदेश में जहरीली शराब से मौतों के बाद छत्तीसगढ़ आबकारी आयुक्त ने अवैध महुआ शराब विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत उड़नदस्ता टीम लगातार गश्त कर रही है। इसी क्रम में 12 सितंबर को मुखबिर ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता को सूचना दी कि न्यायालय अंबिकापुर के पीछे ठेला लगाकर खुलेआम महुआ शराब बेचने वाला राजेंद्र सिंह सरदार मठपारा से महुआ शराब लेने गया है। सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर करसू तालाब के पास उसे पकड़ा, और उसकी स्कूटी वाहन में रखी दो बोरियों से 21 लीटर महुआ शराब जब्त किया। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59(क) के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। पूर्व में भी इसे महुआ शराब के मामले में जेल भेजा जा चुका है, फिर भी इसके आदत में सुधार नहीं आया है। यह आदतन अपराधी है। कार्रवाई में प्रधान आबकारी आरक्षक अशोक सोनी, नगर सैनिक गणेश पांडे, रणविजय सिंह और रोहित सोनवानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

फांसी लगाकर छात्रा की खुदकुशी, छात्र नेता पर ब्लैकमेल का आरोप

शौचालय में फंदे पर लटकी मिली, स्वजन ने लगाए गंभीर आरोप

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। गांधीनगर थाना क्षेत्र के पटपरिया में अपने जीजा के घर रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही 19 वर्षीय छात्रा ने शुक्रवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतरवाकर मामले की जांच शुरू की। छात्रा के स्वजन ने एक छात्र नेता पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर छात्रा ने यह कदम उठाया।

जानकारी के मुताबिक, एमसीबी जिले के चिरमिरी की 19 वर्षीय अंतरा शाह पिता सर्वजीत शाह अंबिकापुर के पटपरिया में अपने जीजा नीलेश गुप्ता के घर रहकर कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि 12 सितंबर की रात खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चली गई थी। देर रात जीजा के उठने पर उन्होंने छात्रा को कमरे में नहीं पाया। इसकी जानकारी उन्होंने अपनी पत्नी को दी। इसके बाद छात्रा की तलाश की गई तो वह बाथरूम में फंदे पर लटकी मिली। घटना की सूचना गांधीनगर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

छह माह पहले आई थी अंबिकापुर

परिजनों का आरोप है कि छात्रा करीब छह माह पहले अंबिकापुर आई थी और बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। इसी दौरान एक छात्र नेता द्वारा उसे कथित तौर पर ब्लैकमेल किया जा रहा था। परिजनों के अनुसार छात्र नेता के मोबाइल में छात्रा से संबंधित कुछ चैट या वीडियो थे और इन्हें परिजनों को दिखाने की धमकी देकर उसे परेशान किया जा रहा था। परिजनों ने आशंका जताई है कि लगातार दबाव और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हालांकि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। मामले में परिजनों ने छात्र नेता के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि छात्रा की मौत के मामले में सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दरीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर